



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज, शनिवार, 31 दिसम्बर, 2022 ई० (पौष 10, 1944 शक संवत्) [संख्या 53

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गज़ट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	1035—1046	3075	भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1051—1072	1500	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियाँ, भारत सरकार के गज़ट और दूसरे राज्यों के गज़टों का उद्धरण	..	975	भाग 6—क—भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख—नगर पंचायत, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	..	975	भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		975
			भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
			भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ	..	
			भाग 8—सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	675—698	975
			स्टोर्स—पर्वज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

प्रशासनिक सुधार विभाग**अनुभाग-1****[अधि0]****नियुक्ति**

07 सितम्बर, 2022

सं0 542/43-1-2022-25(20)/15—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा आयोजित शोध अधिकारी सीधी भर्ती, चयन, विज्ञापन संख्या 02/2020-21, विभाग संख्या एस-10/3 के आधार पर प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में शोध अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्रीमती कृति सिंह पुत्री श्री भंवरपाल सिंह (रजिस्ट्रेशन संख्या 53600311812) की प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में शोध अधिकारी पे मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500 के पद पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

1—अभ्यर्थी की सेवायें समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सुधार निदेशालय, राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 1993 में उल्लिखित प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

2—अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परीक्षा नियमावली, 2013 एवं सहपठित तदविषयक उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत शोध अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

3—अभ्यर्थी के समस्त प्रमाण-पत्रों यथा वांछित शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जायेगा। कोई अभ्यर्थी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर चयनित होने में सफल हो गया है, तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन विधि शून्य माना जायेगा तथा नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी। सम्बन्धित अभ्यर्थी इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होगा एवं भविष्य में उक्त पद के लिये उसका कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।

4—अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अन्य सेवा सम्बन्धी शर्तों/संगत अभिलेखों को असत्य पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताये सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय/अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

5—ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं, उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2—उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुये श्रीमती कृति सिंह को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वे प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में शोध अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1(अधि0), कक्ष संख्या-305, तृतीय तल, श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों :

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

(ख) प्रशासनिक सुधार निदेशालय एवं उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत किसी व्यक्ति से सम्बन्धित होने की दशा में घोषणा।

(ग) अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

- (घ) निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।
- (ङ) एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।
- (च) इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा।
- (छ) वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।
- (ज) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।
- (झ) भारतीय संविधान में निष्ठा के संबंध में शपथ-पत्र/घोषणा-पत्र।

3—यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि श्रीमती कृति सिंह निर्धारित अवधि में वांछित सूचनाओं/अभिलेखों के साथ कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होती हैं तो यह मानते हुये कि वे नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं, नियमानुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

4—उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये उन्हें कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

सं0 543/43-1-2022-25(20)/15—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा आयोजित शोध अधिकारी सीधी भर्ती, चयन, विज्ञापन संख्या 02/2020-21, विभाग संख्या एस-10/3 के आधार पर प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में शोध अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री विक्रम सिंह भदौरिया (रजिस्ट्रेशन संख्या 53600146528) की प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में शोध अधिकारी पे मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500 के पद पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

1—अभ्यर्थी की सेवायें समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सुधार निदेशालय, राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 1993 में उल्लिखित प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

2—अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परीक्षा नियमावली, 2013 एवं सहपठित तदविषयक उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत शोध अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

3—अभ्यर्थी के समस्त प्रमाण-पत्रों यथा वांछित शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जायेगा। कोई अभ्यर्थी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर चयनित होने में सफल हो गया है, तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन विधि शून्य माना जायेगा तथा नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी। सम्बन्धित अभ्यर्थी इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होगा एवं भविष्य में उक्त पद के लिये उसका कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।

4—अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अन्य सेवा सम्बन्धी शर्तों/संगत अभिलेखों को असत्य पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताये सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय/अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

5—ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं, उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2—उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुये श्रीमती सुनीता सिंह को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वे प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में शोध अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1(अधि0), कक्ष संख्या-305, तृतीय तल, श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों :

- (क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

(ख) प्रशासनिक सुधार निदेशालय एवं उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत किसी व्यक्ति से सम्बन्धित होने की दशा में घोषणा।

(ग) अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

(घ) निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

(ङ) एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

(च) इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा।

(छ) वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(ज) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।

(झ) भारतीय संविधान में निष्ठा के संबंध में शपथ-पत्र/घोषणा-पत्र।

3—यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता सिंह निर्धारित अवधि में वांछित सूचनाओं/अभिलेखों के साथ कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होती हैं तो यह मानते हुये कि वे नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं, नियमानुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

4—उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये उन्हें कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

सं0 544/43-1-2022-25(20)/15—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा आयोजित शोध अधिकारी सीधी भर्ती, चयन, विज्ञापन संख्या 02/2020-21, विभाग संख्या एस-10/3 के आधार पर प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में शोध अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री विपिन यादव पुत्र श्री जगदीश प्रसाद यादव (रजिस्ट्रेशन संख्या 53600340355) की प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में शोध अधिकारी पे मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500 के पद पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

1—अभ्यर्थी की सेवायें समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सुधार निदेशालय, राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 1993 में उल्लिखित प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

2—अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परीक्षा नियमावली, 2013 एवं सहपठित तदविषयक उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत शोध अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

3—अभ्यर्थी का नियमानुसार चरित्र सत्यापन एवं पुलिस सत्यापन कराया जा रहा है। उक्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उनकी नियुक्ति विधि शून्य मानी जायेगी तथा नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी।

4—अभ्यर्थी के समस्त प्रमाण-पत्रों यथा वांछित शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जायेगा। कोई अभ्यर्थी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर चयनित होने में सफल हो गया है, तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन विधि शून्य माना जायेगा तथा नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी। सम्बन्धित अभ्यर्थी इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होगा एवं भविष्य में उक्त पद के लिये उसका कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।

5—अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अन्य सेवा सम्बन्धी शर्तों/संगत अभिलेखों को असत्य पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताये सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय/अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

6—ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं, उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2—उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुये श्री विपिन यादव को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वे प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में शोध अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1(अधि0), कक्ष संख्या-305, तृतीय तल, श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों :

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

(ख) प्रशासनिक सुधार निदेशालय एवं उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत किसी व्यक्ति से सम्बन्धित होने की दशा में घोषणा।

(ग) अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

(घ) निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

(ङ) एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

(च) इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा।

(छ) वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(ज) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।

(झ) भारतीय संविधान में निष्ठा के संबंध में शपथ-पत्र/घोषणा-पत्र।

3—यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि श्री विपिन यादव निर्धारित अवधि में वांछित सूचनाओं/अभिलेखों के साथ कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होती हैं तो यह मानते हुये कि वे नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं, नियमानुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

4—उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये उन्हें कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

सं0 545/43-1-2022-25(20)/15—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा आयोजित शोध अधिकारी सीधी भर्ती, चयन, विज्ञापन संख्या 02/2020-21, विभाग संख्या एस-10/3 के आधार पर प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में शोध अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी सुश्री अनुपमा यादव पुत्री श्री सुरेश बाबू यादव (रजिस्ट्रेशन संख्या 53600340063) की प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में शोध अधिकारी पे मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500 के पद पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

1—अभ्यर्थी की सेवायें समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सुधार निदेशालय, राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 1993 में उल्लिखित प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

2—अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परीक्षा नियमावली, 2013 एवं सहपठित तदविषयक उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत शोध अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

3—अभ्यर्थी का नियमानुसार चरित्र सत्यापन एवं पुलिस सत्यापन कराया जा रहा है। उक्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उनकी नियुक्ति विधि शून्य मानी जायेगी तथा नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी।

4—अभ्यर्थी के समस्त प्रमाण-पत्रों यथा वांछित शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जायेगा। कोई अभ्यर्थी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर चयनित होने में सफल हो गया है, तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन विधि शून्य माना जायेगा तथा नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी। सम्बन्धित अभ्यर्थी इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होगा एवं भविष्य में उक्त पद के लिये उसका कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।

5—अभ्यर्थी के सम्बन्ध में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अन्य सेवा सम्बन्धी शर्तों/संगत अभिलेखों को असत्य पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताये सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय/अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

6—ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं, उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2—उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुये सुश्री अनुपमा यादव को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वे प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में शोध अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1(अधि0), कक्ष संख्या-305, तृतीय तल, श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों :

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

(ख) प्रशासनिक सुधार निदेशालय एवं उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत किसी व्यक्ति से सम्बन्धित होने की दशा में घोषणा।

(ग) अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

(घ) निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

(ङ) एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

(च) इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा।

(छ) वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(ज) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।

(झ) भारतीय संविधान में निष्ठा के संबंध में शपथ-पत्र/घोषणा-पत्र।

3—यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि सुश्री अनुपमा यादव निर्धारित अवधि में वांछित सूचनाओं/अभिलेखों के साथ कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होती हैं तो यह मानते हुये कि वे नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं, नियमानुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

4—उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये उन्हें कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

आज्ञा से,
कै० रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-1

तैनाती

11 अक्टूबर, 2022

सं० राज्य कर-1-1425/11-2022-13/2020—श्री कृष्ण कान्त उपाध्याय, अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, लखनऊ जोन—प्रथम, लखनऊ को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, इटावा जोन, इटावा के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं० राज्य कर-1-1426/11-2022-13/2020—श्री सुनील कुमार राय, अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, गोरखपुर जोन, गोरखपुर को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, लखनऊ जोन—प्रथम, लखनऊ के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1427/11-2022-13/2020—श्री विमल कुमार राय, अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, इटावा जोन, इटावा को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, गोरखपुर जोन, गोरखपुर के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1428/11-2022-13/2020—श्री राम सनेही विद्यार्थी, अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील-तृतीय) राज्य कर, गाजियाबाद को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0षा0) राज्य कर, अयोध्या के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1429/11-2022-13/2020—श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव-II, अपर आयुक्त ग्रेड-2 अपील-प्रथम राज्य कर, अयोध्या को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील द्वितीय) राज्य कर, गाजियाबाद के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1430/11-2022-13/2020—श्री दुर्गेश चन्द्र श्रीवास्तव, अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील-तृतीय) राज्य कर, प्रयागराज को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील) राज्य कर, अलीगढ़ के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1431/11-2022-13/2020—श्री उमा शंकर दुबे, अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0षा0) राज्य कर, गाजियाबाद जोन-द्वितीय, गाजियाबाद को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 राज्य कर एवं संयुक्त सचिव-I, राज्य कर, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1432/11-2022-13/2020—श्री सत्य नारायण, अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0षा0) राज्य कर, इटावा को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील-षष्ठम) राज्य कर, कानपुर के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1433/11-2022-13/2020—श्री अनूप कुमार माहेश्वरी, अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0षा0) राज्य कर, अलीगढ़ को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 राज्य कर एवं संयुक्त सचिव-II, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1434/11-2022-13/2020—श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, अपर आयुक्त ग्रेड-2 अपील-5, राज्य कर, गाजियाबाद को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0षा0) राज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1435/11-2022-13/2020—श्री उदय प्रताप सिंह-II, अपर आयुक्त ग्रेड-2 अपील-प्रथम, राज्य कर, गाजियाबाद को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0षा0) राज्य कर, अलीगढ़ के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1436/11-2022-13/2020—श्री शशांक शेखर मिश्रा, अपर आयुक्त ग्रेड-2 अपील—तृतीय, राज्य कर, लखनऊ को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील-द्वितीय) राज्य कर, गोरखपुर के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1437/11-2022-13/2020—श्री ओमप्रकाश चौबे, अपर आयुक्त ग्रेड-2 अपील—द्वितीय, राज्य कर, गाजियाबाद को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0षा0) राज्य कर, इटावा के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1438/11-2022-13/2020—श्री रमाशंकर द्विवेदी, अपर आयुक्त ग्रेड-2 अपील—तृतीय, राज्य कर, वाराणसी को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0षा0) राज्य कर, झांसी के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1439/11-2022-13/2020—श्री मारुति शरण चौबे, अपर आयुक्त ग्रेड-2 अपील—द्वितीय, राज्य कर, अयोध्या को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0षा0) राज्य कर, सहारनपुर के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1440/11-2022-13/2020—श्री अमरनाथ यादव-II, अपर आयुक्त ग्रेड-2 अपील—द्वितीय, राज्य कर, वाराणसी को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील) राज्य कर, मुजफ्फरनगर के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1441/11-2022-13/2020—श्री राम कुबेर, अपर आयुक्त ग्रेड-2 अपील—पंचम, राज्य कर, लखनऊ को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0षा0) राज्य कर, वाराणसी जोन—द्वितीय, वाराणसी के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1442/11-2022-13/2020—श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह, अपर आयुक्त ग्रेड-2 अपील—द्वितीय, राज्य कर, नोएडा को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0षा0) राज्य कर, वाराणसी जोन—प्रथम, वाराणसी के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1443/11-2022-13/2020—श्री राजेश कुमार पाण्डेय-I, अपर आयुक्त ग्रेड-2 अपील—प्रथम, राज्य कर, मेरठ को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0षा0) राज्य कर, लखनऊ जोन—द्वितीय, लखनऊ के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1444/11-2022-13/2020—श्री हरिनाथ सिंह, अपर आयुक्त ग्रेड-2 अपील—प्रथम राज्य कर, प्रयागराज को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील प्रथम) राज्य कर, मेरठ के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं० राज्य कर-1-1445/11-2022-13/2020—श्री हरिराम, अपर आयुक्त ग्रेड-2 अपील-द्वितीय, राज्य कर, बरेली को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि०अनु०षा०) राज्य कर, प्रयागराज के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं० राज्य कर-1-1446/11-2022-13/2020—श्री कैलाश नारायण, अपर आयुक्त ग्रेड-2 अपील-तृतीय, राज्य कर, आगरा को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील तृतीय) राज्य कर, वाराणसी के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं० राज्य कर-1-1447/11-2022-13/2020—श्री धीरेन्द्र प्रताप, अपर आयुक्त ग्रेड-2 अपील, राज्य कर, इटावा को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील प्रथम) राज्य कर, झांसी के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं० राज्य कर-1-1448/11-2022-13/2020—श्री अशोक कुमार पाण्डेय, अपर आयुक्त ग्रेड-2 अपील प्रथम, राज्य कर, झांसी को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील) राज्य कर, मिर्जापुर के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं० राज्य कर-1-1449/11-2022-13/2020—श्री कृष्ण प्रताप, अपर आयुक्त ग्रेड-2 अपील, राज्य कर, मुजफ्फरनगर को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील पंचम) राज्य कर, लखनऊ के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं० राज्य कर-1-1450/11-2022-13/2020—श्री राम बाबू, अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि०अनु०षा०), राज्य कर, सहारनपुर को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील प्रथम) राज्य कर, मुरादाबाद के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं० राज्य कर-1-1452/11-2022-13/2020—श्री आनन्द कुमार सिंह-I, अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि०अनु०षा०), राज्य कर, प्रयागराज को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील तृतीय) राज्य कर, गाजियाबाद के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं० राज्य कर-1-1453/11-2022-13/2020—श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि०अनु०षा०), राज्य कर, वाराणसी जोन-प्रथम, वाराणसी को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील पंचम) राज्य कर, कानपुर के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं० राज्य कर-1-1454/11-2022-13/2020—श्री शशि भूषण सिंह-I, अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि०अनु०षा०), राज्य कर, मेरठ को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील द्वितीय) राज्य कर, नोएडा के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1455/11-2022-13/2020—श्री भूपेन्द्र शुक्ला, अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0षा0), राज्य कर, लखनऊ जोन—द्वितीय, लखनऊ को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील चतुर्थ) राज्य कर, गाजियाबाद के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1456/11-2022-13/2020—श्री राजेश सिंह, अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0षा0), राज्य कर, गोरखपुर को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील तृतीय) राज्य कर, लखनऊ के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1457/11-2022-13/2020—श्री ललित मिश्रा, अपर आयुक्त ग्रेड-2 अपील, राज्य कर, सहारनपुर को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील—प्रथम) राज्य कर, नोएडा के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1458/11-2022-13/2020—श्री ओम प्रकाश तिवारी, अपर आयुक्त ग्रेड-2 एवं संयुक्त सचिव-1, राज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0षा0), राज्य कर, गाजियाबाद जोन—द्वितीय, गाजियाबाद के पद/स्थान पर स्थानान्तरित करते हुये एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1459/11-2022-13/2020—श्री दीनानाथ, नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2 (तत्कालीन संयुक्त आयुक्त, वि0अनु0षा0, रेंज-बी, राज्य कर, वाराणसी) को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील-द्वितीय), राज्य कर, अयोध्या के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1460/11-2022-13/2020—श्री नन्हू लाल सोनी, नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2 (तत्कालीन संयुक्त आयुक्त, वि0अनु0षा0, राज्य कर, बिजनौर) को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील), राज्य कर, सहारनपुर के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1461/11-2022-13/2020—श्री जय प्रकाश नारायण पटेल, नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2 (तत्कालीन संयुक्त आयुक्त, वि0अनु0षा0, रेंज-ए, राज्य कर, सहारनपुर) को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील), राज्य कर, इटावा के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1462/11-2022-13/2020—श्री राम प्रवेश प्रसाद, नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2 (तत्कालीन संयुक्त आयुक्त, कार्यपालक, सम्भाग-बी, राज्य कर, गाजियाबाद) को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील-तृतीय), राज्य कर, कानपुर के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं0 राज्य कर-1-1463/11-2022-13/2020—श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2 (तत्कालीन संयुक्त आयुक्त, कार्यपालक, राज्य कर, गोण्डा) को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील-द्वितीय), राज्य कर, मेरठ के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं० राज्य कर-1-1464/11-2022-13/2020—श्री सर्वजीत, नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2 (तत्कालीन संयुक्त आयुक्त, वि०अनु०षा०, रेंज-ए, राज्य कर, प्रयागराज) को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि०अनु०षा०), राज्य कर, आगरा के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं० राज्य कर-1-1465/11-2022-13/2020—श्री सुभाष चन्द्र-2, नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2 (तत्कालीन संयुक्त आयुक्त, कार्यपालक, सम्भाग-ए, राज्य कर, गोरखपुर) को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील-द्वितीय), राज्य कर, बरेली के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं० राज्य कर-1-1466/11-2022-13/2020—श्री महेन्द्र विक्रम सिंह, नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2 (तत्कालीन संयुक्त आयुक्त, कार्पोरेट सेल, राज्य कर, गाजियाबाद-1) को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि०अनु०षा०), राज्य कर, कानपुर जोन-द्वितीय, कानपुर के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं० राज्य कर-1-1467/11-2022-13/2020—श्री राम प्रकाश-III, नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2 (तत्कालीन संयुक्त आयुक्त, कार्पोरेट सेल, राज्य कर, सहारनपुर, मुख्यालय—मुजफ्फरनगर) को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील-प्रथम), राज्य कर, कानपुर के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं० राज्य कर-1-1468/11-2022-13/2020—श्री हंस कुमार, नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2 (तत्कालीन संयुक्त आयुक्त, कार्पोरेट सेल, राज्य कर, गाजियाबाद-2) को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील), राज्य कर, सीतापुर के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं० राज्य कर-1-1469/11-2022-13/2020—श्री विजय प्रकाश राम, नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2 (तत्कालीन संयुक्त आयुक्त, कार्पोरेट सेल, राज्य कर, कानपुर-2) को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील-तृतीय), राज्य कर, आगरा के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं० राज्य कर-1-1470/11-2022-13/2020—श्री राजेश कुमार-V, नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2 (तत्कालीन संयुक्त आयुक्त, कार्पोरेट सेल, राज्य कर, वाराणसी-1) को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील), राज्य कर, बुलन्दशहर के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं० राज्य कर-1-1471/11-2022-13/2020—श्री सोनेलाल दोहरे, नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2 (तत्कालीन संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ) को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील-प्रथम), राज्य कर, गाजियाबाद के पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं० राज्य कर-1-1472/11-2022-13/2020—श्री राजाराम गुप्ता, नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2 (तत्कालीन संयुक्त आयुक्त, वि०अनु०षा० रेंज-ए, राज्य कर, कानपुर) को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि०अनु०षा०), राज्य कर, नोएडा के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं० राज्य कर-1-1473/11-2022-13/2020—श्री श्रीमती रूबी सिंह—I, नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2 (तत्कालीन संयुक्त आयुक्त, टैक्स ऑडिट, राज्य कर, नोएडा) को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील-प्रथम), राज्य कर, आगरा के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सं० राज्य कर-1-1474/11-2022-13/2020—श्री देवमणि शर्मा, नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-2 (तत्कालीन संयुक्त आयुक्त, टैक्स ऑडिट, राज्य कर, लखनऊ-1) को तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि०अनु०षा०), राज्य कर, गोरखपुर के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2—उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 31 दिसम्बर, 2022 ई० (पौष 10, 1944 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय,
विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय, जिलाधिकारी, कानपुर देहात

प्रारूप-19

[नियम-27 का उपनियम (11)]

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

[अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अधीन]

अधिसूचना

15 दिसम्बर, 2022 ई०

सं० 2481/आठ-अ०जि०(भू०अ०) कानपुर नगर-चूँकि प्रारम्भिक अधिसूचना सं० 196/आठ-अ०जि० (भू०अ०) कानपुर नगर/दिनांक 02 मई, 2022, लोक प्रयोजन, अर्थात् उप परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु कार्पोरेशन लि० के माध्यम से कानपुर देहात में औरैया कंचौसी, रेलवे स्टेशन के निकट सम्पार संख्या-5सी पर उ०म०रे० के कानपुर टूण्डला सेक्शन के किमी० 1091/7-9डी०एफ०सी०सी० रूट पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु जनपद कानपुर देहात, तहसील डेरापुर के ग्राम रानेपुर, रसूलाबाद की 0.6149 हे० व बान की 0.8378 हे० भूमि सहित कुल 1.4527 हे० भूमि अर्जित करने के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम सं० 30 सन् 2013) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई और राजकीय गजट में दिनांक 28 मई, 2022 को प्रकाशित की गई थी।

उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन उपबन्ध के अनुसरण में प्रस्तुत की गयी कलेक्टर की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (1) के अधीन घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि का क्षेत्रफल लोक प्रयोजन के लिये आवश्यक है और अनुसूची "ख" में यथा-प्रदत्त ग्राम, तहसील और जिला में कोई भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिये चिन्हित नहीं की गयी है (इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)।

राज्यपाल अग्रेतर उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (2) के अधीन जिला कानपुर देहात के कलेक्टर को इस आशय की घोषणा प्रकाशित करने के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना को संक्षिप्त रूप में प्रकाशित करने के लिये निर्देश देते हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है। (जिला कानपुर देहात में औरैया कंचौसी रेलवे स्टेशन के निकट सम्पार संख्या-5सी पर उ०म०रे० के कानपुर-टूण्डला सेक्शन के किमी० 1091/7-9डी०एफ०सी०सी० रूट पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु भूमि अर्जन से किसी परिवार का विस्थापित होना संभाव्य नहीं है।) अतएव पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु कोई भूमि चिन्हित करने और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश के प्रकाशित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची "क"

प्रस्तावित अर्जनाधीन भूमि

क्र०सं०	जनपद	तहसील	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
1	कानपुर देहात	डेरापुर	रानेपुर रसूलाबाद	488	0.1539
2				264-मि०	0.0364
3				268	0.0607
4				269-मि०	0.0384
5				262	0.0420
6				270-मि०	0.2430
7				272	0.0405
8				योग..	0.6149
9			बान	145	0.1051
10				144	0.0931
11				143	0.0607
12				142-मि०	0.3272
13				47	0.0250
14				52	0.0729
15				53	0.0607
16				54	0.0931
17				योग..	0.8378
				कुल योग..	1.4527

अनुसूची "क"

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

क्र० सं०	जनपद	तहसील	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
1	कानपुर देहात	डेरापुर	रानेपुर रसूलाबाद व बान	शून्य	शून्य

(इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना संभाव्य नहीं है)

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर/अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्यापित) 37/17 वेस्टकाट भवन, माल रोड कानपुर नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह०) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी,
कानपुर देहात।

Form-19
[Sub-rule (1) of rule 27]
Declaration by Appropriate Government/Collector
[Under Sub-section (1) of section-19 of the Act]

NOTIFICATION
December 15, 2022

No. 2481/VIII/A.D.M.(L.A.) Kanpur Nagar—Since the initial notification No. 196/VIII-A.D.M.(L.A.) Kanpur Nagar/ Dated May 02, 2022 for public purpose, through near Auraiya-Kanchausi Railway Station in the countryside at Crossing no. -5c of Kanpur-Tundla section of NCR on DFCC route km. 1091/7-9 for the construction of 2 lane rail over bridge, proper compensation and transparency in land acquisition, Rehabilitation and Resettlement in respect of a total of 1.4527 hectares including 0.6149 hectares of Village Ranepur Rasulabad and 0.8378 hectares of Village-Baan, Derapur Tehsil of Kanpur Dehat District. The Rights Act-2013 (Act no. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act) was issued under sub-section (1) of section 11 and was published in the Official Gazette on May 28, 2022.

Therefore, now after considering the report of the Collector submitted in pursuance of the provision under Sub-section (2) of section 15 of the said Act, the Governor has made a declaration under Sub-section (1) of section 19 of the said Act, that they are satisfied that the area of land mentioned in Schedule "A" below is necessary for a public purpose and that any land in the Village, Tehsil and District as provided in Schedule "B" for Rehabilitation and Resettlement of displaced families has not been identified (no family is likely to be displaced due to land acquisition for this project).

The Governor further instructs the Collector to publish the Rehabilitation and Resettlement plan in a brief form along with publishing a declaration to this effect under Sub-section (2) of section 19 of the said Act. Summary of Rehabilitation and Resettlement Plan is attached herewith (No family is likely to be displaced due to land acquisition for Auraiya-Kanchausi Railway Station in the countryside at crossing no.-5c of Kanpur-Tundla section of NCR on DFCC route Km. 1091/7-9 for the construction of 2 lane rail over bridge, proper compensation and transparency in land acquisition, Rehabilitation and Resettlement). There is no need to publish.

SCHEDULE "A"
(Land Under Proposed Acquisition)

Sl. no.	District	Tehsil	Village	Gata no.	Proposed area for acquisition
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectares</i>
1	Kanpur Dehat	Derapur	Ranepur Rasulabad	488	0.1539
2				264-M	0.0364
3				268	0.0607
4				269-M	0.0384
5				262	0.0420
6				270-M	0.2430
7				272	0.0405
8				Total ..	0.6149
9			Baan	145	0.1051
10				144	0.0931
11				143	0.0607
12				142-M	0.3272
13				47	0.0250
14				52	0.0729
15				53	0.0607
16				54	0.0931
17				Total ..	0.8378
18				Grand Total ..	1.4527

SCHEDULE "B"
(Land Marked as Settlement Area for Displaced Families)

Sl. no.	District	Tehsil	Village	Gata no.	Proposed area for acquisition
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectares</i>
1	Kanpur Dehat	Derapur	Ranepur Rasulabad & Baan	Nil	Nil

(No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project).

Note : Site map of the said land can be seen in the Office of Collector/Additional District Magistrate (Land Acquisition) 37/17 westcott building, Mall Road, Kanpur Nagar.

(Sd.) ILLEGIBLE,
Collector,
Kanpur Dehat.

कार्यालय, जिलाधिकारी महोबा

आकार पत्र-1

29 जनवरी 2022 ई०

सं० 358/डी०एल०आर०सी०-12ए-पुनर्ग्रहण/2021-22-शासनादेश संख्या-258/रा०-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, मनोज कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र०सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	चरखारी	चरखारी	मिटलेनगंज	25	1.152	श्रेणी-5-1	बाह्य न्यायालय
					60	0.312	कृषि योग्य	चरखारी की स्थापना
					योग . .	1.464	भूमि नवीन परती	हेतु

मनोज कुमार,
जिलाधिकारी,
महोबा।

कार्यालय, जिलाधिकारी मेरठ

04 जनवरी, 2022 ई०

सं० 886/सात-डी०एल०आर०सी०/पन०/2021-शासनादेश संख्या-744/एक-1/2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी प्रयोक्तव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, के० बालाजी, जिलाधिकारी मेरठ निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकारण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा उप जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 03 जनवरी, 2022 के आधार पर अनुसूची के अनुसार उल्लिखित भूमि, शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी व्यवस्थानुसार राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ के निवर्तन पर रखता हूँ।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
मेरठ	मेरठ	मेरठ	गगोल	212	1.0620	कल्लर	माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ के निवर्तन पर रखते हुए राजकीय कन्या इन्टर कॉलेज की स्थापना हेतु।

के० बालाजी,
जिलाधिकारी, मेरठ।

कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ

14 मार्च, 2022 ई०

सं० 1554/आठ/75/2020-22-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-59 तथा शासनादेश सं० 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016, शासनादेश सं०-745/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश सं० 1131/आठ-1-17-08 विविध/2016 दिनांक 11 जुलाई, 2018 तथा उ०प्र० शासन राजस्व अनु०-1, लखनऊ की अधिसूचना सं० 688/एक-1-2020-20(1)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपभोग करते हुए मैं, सुरेन्द्र सिंह, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम रन्हेरा, परगना व तहसील जेवर, जनपद गौतमबुद्ध नगर की 0.2240 हे० ग्राम सभा भूमि को फिर से अपने अधिकार क्षेत्र में लेता हूँ तथा इसी क्रम में जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर के पत्रांक 857/डी०एल०आर०सी०/2021-22 दिनांक 24 फरवरी, 2022 में की गई संस्तुति को दृष्टिगत कर निम्न अनुसूची में अंकित भूमि नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट के परिसर में आ रहे पथवाया नाले की सींच को विस्थापित करने हेतु प्रतिकर की धनराशि अंकन रु० 51,52,000.00 एवं पूंजीकृत मूल्य 1680.00 सहित रु० 51,53,680.00 (अंकन रु० इक्यावन लाख तिरपन हजार छः सौ अस्सी) को निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किये जाने तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-77 के प्राविधानों के अन्तर्गत पुर्नग्रहित सार्वजनिक उपयोग की भूमि के सापेक्ष उतनी ही अथवा उससे अधिक सामान्य श्रेणी की भूमि उसी अथवा निकटवर्ती

ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकारण में आरक्षित करने की शर्त के अधीन नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट के परिसर में आ रहे पथवाया नाले की सींच को विस्थापित करने हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पक्ष में हस्तान्तरित करता हूँ।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खसरा नं०	कुल क्षेत्रफल	विशेष प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुर्नग्रहित की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
गौतमबुद्धनगर	जेवर	जेवर	रन्हेरा	रन्हेरा	1133 मि०	0.2240 (शोर)	नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट के परिसर में आ रहे पथवाया नाले की सींच को विस्थापित करने हेतु

28 मार्च, 2022 ई0

सं० 1641/आठ-68/2020-22—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-59 तथा शासनादेश सं०-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016, शासनादेश सं० 745/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 तथा उ०प्र० शासन राजस्व अनु०-1, लखनऊ की अधिसूचना सं० 688/एक-1-2020-20(1)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपभोग करते हुए मैं, सुरेन्द्र सिंह, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ, जिलाधिकारी, गाजियाबाद के पत्रांक 1348/सात-डी०एल०आर०सी०/विनिमय/गा०बाद/2021, दिनांक 02 दिसम्बर, 2021 में की गई संस्तुति एवं पत्र दिनांक 05 मार्च, 2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या को दृष्टिगत कर निम्न अनुसूची-क में उल्लिखित ग्राम भटजन, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद की ग्राम सभा की 0.8597 हे० सार्वजनिक उपयोग की भूमि को फिर से अपने अधिकार क्षेत्र में लेता हूँ तथा उक्त भूमि पूर्वी डेडीकेटिड फ्रंट कोरिडोर परियोजना हेतु प्रतिकर की धनराशि रु० 49,86,260.00 (अंकन उन्चास लाख छियासी हजार दौ सौ साठ रुपये मात्र) निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किये जाने एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-77 के प्राविधानों के अन्तर्गत पुर्नग्रहित सार्वजनिक उपयोग की भूमि के सापेक्ष पूर्वी डेडीकेटिड फ्रंट कोरिडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० मेरठ की अनुसूची-ख में उल्लिखित ग्राम भटजन, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद स्थित 0.9175 हे० भूमि का विनिमय कर ग्राम सभा ग्राम भटजन, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने की शर्त के अधीन पूर्वी डेडीकेटिड फ्रंट कोरिडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०, मेरठ के पक्ष में हस्तान्तरित की जाती है।

अनुसूची-क

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	प्रयोजन जिसके लिए भूमि विनिमय की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
गाजियाबाद	मोदीनगर	जलालाबाद	भटजन	भटजन	657	1023	0.0043	
					659	1022	0.0108	
					659	710	0.0275	
					659	744	0.0260	
					659	706	0.0210	
					657	705	0.0073	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
					659	604	0.0020	
					672	613	0.1878	पूर्वी डेडीकेटिड
					671	616	0.0050	फ्रंट कोरिडोर
					669	617	0.5185	परियोजना हेतु
					659	629	0.0065	
					659	619	0.00033	
					657	524	0.0067	
					659	607	0.0100	
					659	1012	0.0145	
					659	1007	0.0085	
					योग . .		0.8597	

अनुसूची-ख

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विनिमय के उपरान्त ग्राम सभा के नाम दर्ज करने हेतु
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
गाजियाबाद	मोदीनगर	जलालाबाद	भटजन	भटजन	665	1008	0.0216	
					665	1006	0.0145	
					665	745	0.0120	
					665	743	0.0230	
					665	736	0.0130	ग्रामसभा,
					665	735	0.0135	ग्राम भटजन,
					665	734	0.0152	परगना
					665	704	0.0315	जलालाबाद,
					665	602	0.0030	तहसील
					665	641	0.3160	मोदीनगर,
					665	640	0.3340	जिला
					665	636	0.0613	गाजियाबाद
					665	631	0.0103	के नाम
					665	593	0.0060	राजस्व
					665	528	0.0010	अभिलेखों में
					665	527	0.0054	दर्ज किये
					665	526	0.0079	जाने हेतु
					665	605	0.0283	
					योग . .		0.9175	

28 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 1924/आठ-79/2020-22—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-59 तथा शासनादेश सं0-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016, शासनादेश सं0 745/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 तथा उ0प्र0 शासन राजस्व अनु0-1, लखनऊ की अधिसूचना सं0 688/एक-1-2020-20(1)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपभोग करते हुए मैं, सुरेन्द्र सिंह, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ निम्न अनुसूची के स्तम्भ 6, 7, व 8 (क्रमशः खसरा संख्या/क्षेत्रफल/विवरण) में उल्लिखित ग्राम किल्हौड़ा, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद की 0.2337 हे0 सर्वजनिक उपयोग की भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा इसी क्रम में जिलाधिकारी गाजियाबाद के पत्र सं0 1535/सात-डी0एल0आर0सी0/पूर्ण0/गाजियाबाद/2022 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 में की गई संस्तुति को दृष्टिगत कर निम्न अनुसूची में अंकित भूमि का मूल्यांकन रु0 2,43,06,600.00 एवं परिवर्तन शुल्क अंकन रु0 15,19,050.00 सहित कुल धनराशि रु0 2,58,25,650.00 रुपये (रु0 दो करोड़ अठ्ठावन लाख पच्चीस हजार छः सौ पचास मात्र) निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किये जाने तथा उक्त भूमि के बदले ग्राम किल्हौड़ा, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद स्थित खसरा संख्या 1014, रकबा 1.1047 हे0 (बंजर) भूमि में से 0.0580 हे0, खसरा नम्बर 275 रकबा 0.1520 हे0 (बंजर) भूमि में से 0.0300 हे0 एवं रकबा 0.0934 हे0 तथा खसरा नम्बर 713, रकबा 0.2530 हे0 भूमि (ऊसर) में से 0.0523 हे0 आरक्षित करने की शर्त के अधीन डीएफसीसीआईएल, नई दिल्ली के पक्ष में आवंटित किये जाने हेतु जिलाधिकारी, गाजियाबाद को हस्तान्तरित करता हूँ।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण	प्रयोजन जिसके लिए भूमि विनिमय की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
गाजियाबाद	मोदीनगर	जलालाबाद	किल्हौड़ा	किल्हौड़ा	1377	हेक्टेयर 0.0035	नाली	पूर्वी डेडीकेटिड फ्रंट कोरिडोर परियोजना हेतु
					1375	0.0078	नाली	
					1387	0.0100	चकमार्ग	
					1388	0.0070	नाली	
					1391	0.0084	चकमार्ग	
					1164	0.0115	नाली	
					996	0.0020	नाली	
					941	0.0300	अकृषिक भूमि विजली घर	
					940	0.0580	अकृषिक भूमि स्कूल	
					1113	0.0175	चकमार्ग	
					1013	0.0015	चकमार्ग	
					812	0.0180	चकमार्ग	
					1010	0.0090	चकमार्ग	
					800	0.0290	चकमार्ग	
					805	0.0060	नाली	
					799	0.0145	नाली	
योग					0.2337			

13 मई, 2022 ई0

सं0 2099/आठ-84/2020-22—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-59 तथा शासनादेश सं0 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016, शासनादेश सं0-745/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 तथा उ0प्र0 शासन राजस्व अनु0-1, लखनऊ की अधिसूचना सं0 688/एक-1-2020-20(1)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपभोग करते हुए मैं, सुरेन्द्र सिंह, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6, 7, व 8 (क्रमशः खसरा संख्या/क्षेत्रफल/विवरण) में उल्लिखित ग्राम भटजन, परगना जालालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद की 0.1124हे0 सार्वजनिक उपयोग की भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा इसी क्रम में जिलाधिकारी, गाजियाबाद के पत्र सं0 1571/सात/डीएलआरसी/पुर्न0/गा0बा/2022, दिनांक 26 अप्रैल, 2022 में की गई संस्तुति को दृष्टिगत कर निम्न अनुसूची में अंकित भूमि का मुल्यांकन रु0 67,44,900.00 एवं परिवर्तन शुल्क अंकन रु0 4,21,500.00 सहित कुल धनराशि रु0 71,66,400.00 रुपये (रु0 इक्वत्तर लाख छियासठ हजार चार सौ मात्र) निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किये जाने तथा उक्त भूमि के बदले ग्राम भटजन, परगना जालालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद स्थित खसरा संख्या 411/0.1080 हे0, 413/0.0440 हे0 कुल रकबा 0.1520 हे0 (ऊसर) में से 0.1124 हे0 भूमि आरक्षित करने की शर्त के अधीन डीएफसीसीआईएल, नई दिल्ली के पक्ष में आवंटित किये जाने हेतु जिलाधिकारी, गाजियाबाद को हस्तान्तरित करता हूँ।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण	प्रयोजन जिसके लिए भूमि विनिमय की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
गाजियाबाद	मोदीनगर	जालालाबाद	भटजन	भटजन	1030	0.0090	नाली	पूर्वी डेडीकेटिड
					1011	0.0070	नाली	फ्रंट कोरिडोर
					607 / 1258	0.0050	नाली	परियोजना हेतु
					609	0.0020	चकमार्ग	
					610	0.0010	नाली	
					630	0.0033	नाली	
					618	0.0017	नाली	
					588	0.0235	चकमार्ग	
					568	0.0308	चकमार्ग	
					589	0.0118	नाली	
					523	0.0133	चकमार्ग	
					625	0.0040	नाली	
					योग	0.1124		

आज्ञा से
सुरेन्द्र सिंह,
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

कार्यालय, जिलाधिकारी, गाजियाबाद

विज्ञप्ति/आदेश

08 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 1536/सात-डी0एल0आर0सी0-गा0बाद/पुनर्ग्रहण-2021-उप जिलाधिकारी मोदीनगर के पत्र संख्या 1072/र0का0-मोदीनगर/2022, दिनांक 06 अप्रैल, 2022 के आलोक में एवं व्यापक जनहित के दृष्टिगत शासनादेश संख्या 744/एक-1/2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा-2 सपठित धारा 101 एवं उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ की अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी, गाजियाबाद ग्राम भोजपुर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में स्थित श्रेणी 6-1 के अन्तर्गत नाली खाते में दर्ज गाटा संख्या 1495 रकबा 0.0027 हे0 के बदले उसी प्रयोजन हेतु ग्राम भोजपुर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में स्थित बंजर खाते में दर्ज गाटा संख्या 41 मि0/0.2560 हे0 में से रकबा 0.0027 हे0 जो श्रेणी 5-3-ड के अन्तर्गत दर्ज है, को आरक्षित करते हुये प्रस्तावित भूमि के सशुल्क श्रेणी परिवर्तन तथा उक्त संहिता की धारा 59 की उपधारा 4 (ग) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये श्रेणी परिवर्तित की गयी भूमि गाटा संख्या 1495 रकबा 0.0027 हे0 स्थित ग्राम भोजपुर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद का पूर्वी डेडीकेटिड फ्रंट कोरीडोर परियोजना हेतु पुनर्ग्रहण करते हुये लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन के निर्वतन पर रखे जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करता हूँ।

1-ग्राम भोजपुर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में स्थित ग्राम सभा की गाटा संख्या 1495 रकबा 0.0027 हे0 भूमि का सशुल्क श्रेणी परिवर्तन पूर्वी डेडीकेटिड फ्रंट कोरीडोर परियोजना हेतु अपरिहार्य परिस्थितियों में किया जा रहा है। शासनादेश संख्या 745/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 के प्रस्तर-4 (3) के अनुसार डेडीकेटिड फ्रंट कोरीडोर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि0 भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि अंकन रुपये 23,625.00 (तेईस हजार छः सौ पच्चीस रुपये) निर्धारित लेखा शीर्षक "0029-भू-राजस्व-800-अन्य प्राप्तियां-08-मालिकाना राजस्व-806-प्रकीर्ण प्राप्तियां" के नाम जमा कराया जायेगा।

2-शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 के प्रस्तर-4 (1)(ग) के अनुसार पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया लेखाशीर्षक में लेखा शीर्षक "0029-भू-राजस्व-800-अन्य प्राप्तियां-08-मालिकाना राजस्व-806-प्रकीर्ण प्राप्तियां" में जमा कराया जायेगा। तदनुसार भूमि का मूल्य अंकन रुपये 3,78,000.00 तथा पूंजीकृत मूल्य 21.00 रुपये कुल अंकन रुपये 3,78,021.00 (तीन लाख अठत्तर हजार इक्कीस रुपये) निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने के उपरान्त ही कब्जा हस्तान्तरित किया जायेगा।

3-उप-जिलाधिकारी, मोदीनगर द्वारा ग्राम भोजपुर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद स्थित विनिमय के माध्यम से प्राप्त भूमि को नाली के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सकें।

4-पुनर्ग्रहीत की जा रही भूमि का उपयोग, निर्धारित उपयोग से इत्तर नहीं किया जायेगा। यदि भूमि का प्रयोग अन्य प्रयोजन हेतु किया जायेगा तो शर्तों के उल्लंघन की दशा में भूमि का पुनर्ग्रहण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

सं0 1537/सात-डी0एल0आर0सी0-गा0बाद/पुनर्ग्रहण-2021-उप जिलाधिकारी मोदीनगर के पत्र संख्या 1039/र0का0-मोदीनगर/2022, दिनांक 31 मार्च, 2022 के आलोक में एवं व्यापक जनहित के दृष्टिगत शासनादेश संख्या 744/एक-1/2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा-2 सपठित धारा 101 एवं उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ की अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी, गाजियाबाद ग्राम भदौला, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में स्थित श्रेणी 6-2 के अन्तर्गत चकमार्ग खाते में दर्ज गाटा संख्या 316 रकबा 0.0300 हे0 के बदले उसी प्रयोजन हेतु ग्राम भदौला, परगना जलालाबाद, तहसील

मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में स्थित बंजर खाते में दर्ज गाटा संख्या 377 रकबा 0.0300 हे० जो श्रेणी 5-3-ड के अन्तर्गत दर्ज है, को आरक्षित करते हुये प्रस्तावित भूमि के सशुल्क श्रेणी परिवर्तन तथा उक्त संहिता की धारा 59 की उपधारा 4 (ग) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये श्रेणी परिवर्तित की गयी भूमि गाटा संख्या 316 रकबा 0.0300 हे० स्थित ग्राम भदौला, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद का पूर्वी डेडीकेटिड फ्रंट कोरीडोर परियोजना हेतु पुनर्ग्रहण करते हुये लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन के निर्वर्तन पर रखे जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करता हूँ।

1—ग्राम भदौला, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में स्थित ग्राम सभा की गाटा संख्या 316 रकबा 0.0300 हे० भूमि का सशुल्क श्रेणी परिवर्तन पूर्वी डेडीकेटिड फ्रंट कोरीडोर परियोजना हेतु अपरिहार्य परिस्थितियों में किया जा रहा है। शासनादेश संख्या 745/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 के प्रस्तर-4 (3) के अनुसार डेडीकेटिड फ्रंट कोरीडोर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि अंकन रुपये 1,12,500.00 (एक लाख बारह हजार पांच सौ रुपये) निर्धारित लेखा शीर्षक "0029—भू-राजस्व—800—अन्य प्राप्तियां—08—मालिकाना राजस्व—806—प्रकीर्ण प्राप्तियां" के नाम जमा कराया जायेगा।

2—शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 के प्रस्तर-4 (1)(ग) के अनुसार पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया लेखाशीर्षक में लेखा शीर्षक "0029—भू-राजस्व—800—अन्य प्राप्तियां—08—मालिकाना राजस्व—806—प्रकीर्ण प्राप्तियां" में जमा कराया जायेगा। तदनुसार भूमि का मूल्य अंकन रु० 18,00,000.00 तथा पूंजीकृत मूल्य रु० 225.00 कुल अंकन रु० 18,00,225.00 (अठारह लाख दो सौ पच्चीस रुपये) निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने के उपरान्त ही कब्जा हस्तान्तरित किया जायेगा।

3—उप—जिलाधिकारी, मोदीनगर द्वारा ग्राम भदौला, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद स्थित विनिमय के माध्यम से प्राप्त भूमि को चकमार्ग के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सकें।

4—पुनर्ग्रहीत की जा रही भूमि का उपयोग, निर्धारित उपयोग से इत्तर नहीं किया जायेगा। यदि भूमि का प्रयोग अन्य प्रयोजन हेतु किया जायेगा तो शर्तों के उल्लंघन की दशा में भूमि का पुनर्ग्रहण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

09 मई, 2022 ई०

सं० 1588/सात-डी०एल०आर०सी०/कले०-गा०बाद/2022—शासनादेश संख्या 32/744/एक-1/2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 35/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी, गाजियाबाद निम्न अनुसूची के स्तम्भ 6 व 7 (गाटा संख्या व क्षेत्रफल) में उल्लिखित भूमि, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार स्थानीय प्राधिकारों में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण परियोजना जिसके लिये भूमि का पुनर्ग्रहण किया जा रहा है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	गाजियाबाद	लोनी	लोनी	लोनी (चकबन्दी बहार)	1464/1	0.420	श्रेणी 5-3-ड	उत्तर प्रदेश शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-8 के निर्वर्तन पर रखते हुये तहसील लोनी में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना हेतु।

19 मई, 2022 ई0

सं0 1610/सात-डी0एल0आर0सी0-गा0बाद/पुनर्ग्रहण-2022-उप जिलाधिकारी मोदीनगर के पत्र संख्या 1247/र0का0-मोदीनगर/2022, दिनांक 29 अप्रैल, 2022 के आलोक में एवं व्यापक जनहित के दृष्टिगत शासनादेश संख्या 744/एक-1/2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा-2 सपठित धारा 101 एवं उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ की अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी, गाजियाबाद ग्राम सैदपुर हुसैनपुर डीलना, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में स्थित श्रेणी 6-1 के अन्तर्गत नाली खाते में दर्ज गाटा संख्या 410 रकबा 0.0038 हे0 के बदले उसी प्रयोजन हेतु ग्राम सैदपुर हुसैनपुर डीलना, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में स्थित बंजर खाते में दर्ज गाटा संख्या 30मि0 0.0380 हे0, में से रकबा 0.0038 हे0 जो श्रेणी 5-3-ड के अन्तर्गत दर्ज है, को आरक्षित करते हुये प्रस्तावित भूमि के सःशुल्क श्रेणी परिवर्तन तथा उक्त संहिता की धारा 59 की उपधारा 4 (ग) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये श्रेणी परिवर्तित की गयी भूमि गाटा संख्या 410 रकबा 0.0038 हे0 स्थित ग्राम सैदपुर हुसैनपुर डीलना, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद का पूर्वी डेडीकेटिड फ्रंट कोरीडोर परियोजना हेतु पुनर्ग्रहण करते हुये लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन के निर्वतन पर रखे जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करता हूं।

1-ग्राम सैदपुर हुसैनपुर डीलना, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में स्थित ग्राम सभा की गाटा संख्या 410 रकबा 0.0038 हे0 भूमि का सःशुल्क श्रेणी परिवर्तन पूर्वी डेडीकेटिड फ्रंट कोरीडोर परियोजना हेतु अपरिहार्य परिस्थितियों में किया जा रहा है। शासनादेश संख्या 745/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 के प्रस्तर-4 (3) के अनुसार डेडीकेटिड फ्रंट कोरीडोर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि0 भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि अंकन रु0 33,250.00 (तींतीस हजार दौ सौ पचास रुपये) निर्धारित लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियां-08-मालिकाना राजस्व-806-प्रकीर्ण प्राप्तियां" के नाम जमा कराया जायेगा।

2-शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 के प्रस्तर-4 (1)(ग) के अनुसार पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया लेखाशीर्षक में लेखा शीर्षक "0029-भू-राजस्व-800-अन्य प्राप्तियां-08-मालिकाना राजस्व-806-प्रकीर्ण प्राप्तियां" में जमा कराया जायेगा। तदनुसार भूमि का मूल्य अंकन रुपये 5,32,000.00 तथा पूंजीकृत मूल्य रु0 29.00 रुपये कुल अंकन रु0 5,32,029.00 (पांच लाख बत्तीस हजार उन्तीस रुपये) निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने के उपरान्त ही कब्जा हस्तान्तरित किया जायेगा।

3-उप-जिलाधिकारी, मोदीनगर द्वारा ग्राम सैदपुर हुसैनपुर डीलना, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद स्थित विनिमय के माध्यम से प्राप्त भूमि को नाली के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सकें।

4-पुनर्ग्रहीत की जा रही भूमि का उपयोग, निर्धारित उपयोग से इत्तर नहीं किया जायेगा। यदि भूमि का प्रयोग अन्य प्रयोजन हेतु किया जायेगा तो शर्तों के उल्लंघन की दशा में भूमि का पुनर्ग्रहण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

सं0 1611/सात-डी0एल0आर0सी0-गा0बाद/पुनर्ग्रहण-2022-उप जिलाधिकारी मोदीनगर के पत्र संख्या 1340/र0का0-मोदीनगर/2022, दिनांक 12 मई, 2022 के आलोक में एवं व्यापक जनहित के दृष्टिगत शासनादेश संख्या 744/एक-1/2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा-2 सपठित धारा 101 एवं उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ की अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी, गाजियाबाद ग्राम शकूरपुर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में स्थित श्रेणी 6-1 के अन्तर्गत अकृषिक जलमग्न भूमि खाते में दर्ज गाटा संख्या 40 रकबा 0.0023 हे0 के बदले उसी प्रयोजन हेतु ग्राम शकूरपुर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में स्थित नवीन परती खाते में दर्ज गाटा संख्या 216/0.1020 हे0, में से रकबा

0.0023 हे० जो श्रेणी 5-1 के अन्तर्गत दर्ज है, को आरक्षित करते हुये प्रस्तावित भूमि के सःशुल्क श्रेणी परिवर्तन तथा उक्त संहिता की धारा 59 की उपधारा 4 (ग) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये श्रेणी परिवर्तित की गयी भूमि गाटा संख्या 40 रकबा 0.0023 हे० स्थित ग्राम शकूरपुर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद का पूर्वी डेडीकेटिड फ्रंट कोरीडोर परियोजना हेतु पुनर्ग्रहण करते हुये लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन के निर्वतन पर रखे जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करता हूँ।

1—ग्राम शकूरपुर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में स्थित ग्राम सभा की गाटा संख्या 40 रकबा 0.0023 हे० भूमि का सशुल्क श्रेणी परिवर्तन पूर्वी डेडीकेटिड फ्रंट कोरीडोर परियोजना हेतु अपरिहार्य परिस्थितियों में किया जा रहा है। शासनादेश संख्या 745/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 के प्रस्तर-4 (3) के अनुसार डेडीकेटिड फ्रंट कोरीडोर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि अंकन रु० 8,625.00 (आठ हजार छः सौ पच्चीस रुपये) निर्धारित लेखा शीर्षक "0029—भू-राजस्व—800—अन्य प्राप्तियां—08—मालिकाना राजस्व—806—प्रकीर्ण प्राप्तियां" के नाम जमा कराया जायेगा।

2—शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 के प्रस्तर-4 (1)(ग) के अनुसार पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया लेखाशीर्षक में लेखा शीर्षक "0029—भू-राजस्व—800—अन्य प्राप्तियां—08—मालिकाना राजस्व—806—प्रकीर्ण प्राप्तियां" में जमा कराया जायेगा। तदनुसार भूमि का मूल्य अंकन रु० 1,38,000.00 तथा पूंजीकृत मूल्य रु० 17.00 रुपये कुल अंकन रु० 1,38,017.00 (एक लाख अड़तीस हजार सतरह रुपये) निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने के उपरान्त ही कब्जा हस्तान्तरित किया जायेगा।

3—उप—जिलाधिकारी, मोदीनगर द्वारा ग्राम शकूरपुर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद स्थित विनिमय के माध्यम से प्राप्त भूमि को नाली के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सकें।

4—पुनर्ग्रहीत की जा रही भूमि का उपयोग, निर्धारित उपयोग से इत्तर नहीं किया जायेगा। यदि भूमि का प्रयोग अन्य प्रयोजन हेतु किया जायेगा तो शर्तों के उल्लंघन की दशा में भूमि का पुनर्ग्रहण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

राकेश कुमार सिंह,
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

कार्यालय, जिलाधिकारी, अलीगढ़

आकार पत्र—1

आदेश

28 अप्रैल, 2022 ई०

सं० 1481(v)/डी०एल०आर०सी०—उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग—1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 में नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1/2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सेल्वा कुमारी जे०, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ—6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल के ग्राम सोनोट गोकुलपुर में नमामि गंगे कार्यक्रमान्तर्गत नालों के अशोधित श्राव के शोधन हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट/एम०पी०एस० हेतु शासनादेश संख्या 818/नौ-5-19-56सा/2018, नगर विकास अनुभाग 5 लखनऊ, दिनांक 07 मार्च, 2019 में दी गयी व्यवस्थानुसार नगर

विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करती हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुर्नग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	अलीगढ़	कोल	कोल	सोनोट गोकुलपुर	28 मि० 31 मि०	0.688 1.383	6-4 ऊसर	नमामि गंगे कार्यक्रमान्तर्गत नालों के अशोधित श्राव के शोधन हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट/एम०पी०एस० हेतु। नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ के निर्वतन पर।
योग . .						<u>2.071</u>		

23 मई, 2022 ई०

सं० 1585(4)/डी०एल०आर०सी०-उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 में नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1/2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सेल्वा कुमारी जे०, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील गभाना की नवसृजित नगर पंचायत, बरौली में सम्मिलित ग्राम राजगढ़ी की भूमि को गौशाला निर्माण हेतु पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करती हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुर्नग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	अलीगढ़	गभाना	बरौली	राजगढ़ी	42	0.721	6 (4) ऊसर	गौशाला निर्माण हेतु पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, के निर्वर्तन पर।

सेल्वा कुमारी जे०,
जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

कार्यालय, जिलाधिकारी, बुलन्दशहर

09 मई, 2022 ई०

सं० 149/डी०एल०आर०सी०—इस कार्यालय के आदेश संख्या-763/सात-डी०एल०आर०सी०, दिनांक 19 फरवरी, 1997 द्वारा ग्राम नैथला हसनपुर, परगना बरन, तहसील व जिला बुलन्दशहर स्थित भूमि गाटा संख्या-82-मि० क्षे० 01.00 हे० भूमि, हुडको के वित्तीय सहायता से निर्मित केन्द्र के निर्माण हेतु पुनर्ग्रहित की गई थी।

प्रकरण में सचिव, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक 10508/वि०प्रा०/2021-22 दिनांक 26 अगस्त, 2021 के अन्तर्गत अवगत कराया गया कि “झाझर रोड पर राजस्व ग्राम नैथला हसनपुर, परगना बरन, तहसील व जिला बुलन्दशहर स्थित भूमि गाटा संख्या-82-मि० क्षे० 01.00 हे० जिला प्रशासन द्वारा बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण को दिनांक 19 फरवरी, 1997 में हुडको द्वारा किये जाने वाले अनुदान का उपयोग कर बिल्डिंग सेन्टर (निर्मित केन्द्र) बनाने हेतु पुनर्ग्रहण के माध्यम से निःशुल्क भूमि हस्तान्तरित की गयी थी, किन्तु अपरिहार्य कारणों से प्राधिकरण द्वारा इस भूमि पर बिल्डिंग सेन्टर का निर्माण नहीं किया जा सका। बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण की 60वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04 जून, 2016 में लिये गये निर्णयानुसार अन्य ग्रामों के साथ-साथ ग्राम नैथला हसनपुर को दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। तदक्रम में संबंधित राजस्व ग्राम नैथला हसनपुर औद्योगिक विकास विभाग, अनुभाग-4 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-1921/77-4-12एन-07 (डी० एन० जी० आई० आर०) दिनांक 29 जुलाई, 2017 के अनुसार विशेष निवेश क्षेत्र जिसे दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र कहा गया, में समाविष्ट कर दिया गया है। अन्त में उक्त भूमि पर प्राधिकरण की किसी प्रकार की योजना के क्रियान्वयन न होने एवं उक्त भूमि बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाने के कारण गाटा संख्या 82-मि० क्षेत्रफल 1.0 हे० भूमि को जिला प्रशासन को वापिस अन्तरित किये जाने की कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।”

इस संबंध में उपजिलाधिकारी (सदर), बुलन्दशहर से भी आख्या पत्रांक 1650/एस०टी०-एस०डी०एम०-सदर दिनांक 27 नवम्बर, 2021 प्राप्त की गई, जिसमें अवगत कराया गया है कि “ग्राम नैथला हसनपुर, परगना बरन तहसील व जिला बुलन्दशहर के गाटा संख्या 82-मि० रकबा 1.00 हे० भूमि वर्तमान में बुलन्दशहर खुरजा विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण किये जाते समय उक्त भूमि कोठी नील के नाम से अभिलेखों में दर्ज थी, जिसे प्राधिकरण द्वारा बिल्डिंग सेन्टर बनाने हेतु बुलन्दशहर-खुरजा विकास प्राधिकरण के नाम से अधिग्रहित किया गया था। वर्तमान में उक्त भूमि खाली है तथा प्राधिकरण द्वारा कब्जा कर पिलर लगाये हुए है।

उपरोक्त के आधार पर शासकीय/गांव सभा हित में उक्त भूमि को पुनः पूर्व की भांति ग्राम सभा में निहित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः सचिव, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर की आख्या पत्रांक 10508/वि०प्रा०/2021-22 दिनांक 26 अगस्त, 2021 के आधार पर ग्राम नैथला हसनपुर, तहसील व जिला बुलन्दशहर स्थित भूमि गाटा संख्या 82-मि० क्षे० 01.00 हे० भूमि के इस कार्यालय के पुनर्ग्रहण आदेश संत्रय-763/सात-डी०एल०आर०सी०, दिनांक 19 फरवरी, 1997 द्वारा हुडको के वित्तीय सहायता से निर्मित केन्द्र के निर्माण हेतु किये गये पुनर्ग्रहण को निरस्त करते हुए उक्त भूमि को शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 के प्रस्तर 4(1) के खण्ड (थ) में दिये गये प्राविधानों के अनुपालन में पुनः पूर्व की भांति ग्राम सभा में निहित किया जाता है।

11 मई, 2022 ई०

सं० 154/डी०एल०आर०सी०/2022—शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उ०प्रा० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मैं चन्द्र प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित के स्तम्भ 6 में उल्लिखित

ग्राम रसूलपुर रिठौरी, परगना व तहसील सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। उप जिलाधिकारी, सिकन्द्राबाद द्वारा अपनी आख्या पत्रांक 1885/आ०के० दिनांक 13 अप्रैल, 2022 के द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 13 अप्रैल, 2022 व भू०प्र०सं० के प्रस्ताव दिनांक 06 अप्रैल, 2022 के आधार पर अनुसूची में वर्णित भूमि क्षेत्रफल 1.00 हे० भूमि शासनादेश संख्या 1328/नौ-5-20-56सा/2018 दिनांक 07 अप्रैल, 2020 के अनुपालन में नगर विकास विभाग के नर्वतन में रखते हुये नगरपालिका परिषद्, सिकन्द्राबाद को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की स्थापना हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव/ कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुर्नग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	बुलन्दशहर	सिकन्द्राबाद	सिकन्द्राबाद	रसूलपुर रिठौरी	176	11.369 हे० में से 1.00 हे०	6-4 जो अन्य कारणों से अकृषित हो/ऊसर	नगर विकास विभाग के निर्वतन में रखते हुये नगर पालिका परिषद्, सिकन्द्राबाद को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की स्थापना हेतु।

चन्द्र प्रकाश सिंह,
जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

कार्यालय, जिलाधिकारी, लखनऊ

कार्यालय-ज्ञाप

11 मई, 2022 ई०

सं० 778/प्र०सहा०/2022-ग्राम शेरपुरलवल, परगना-निगोंहा, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ में चकबन्दी समिति का गठन न हो पाने तथा ग्राम में चकबन्दी प्रक्रियायें अवरुद्ध हो जाने के परिस्थितिजन्य कारणों को दृष्टिगत उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, 1954 के नियम-3क(10) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं अभिषेक प्रकाश, जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, लखनऊ ग्राम में चकबन्दी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने हेतु शासकीय कार्य के हित में निम्न प्रकार चकबन्दी कमेटी के गठन की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

1-श्री राजाराम वर्मा पुत्र मंगल प्रसाद	अध्यक्ष
2-श्री अरविन्द कुमार सिंह पुत्र शमशेर बहादुर सिंह	सदस्य
3-श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री द्वारिका सिंह	सदस्य
4-श्री दलजीत सिंह पुत्र श्री जगत प्रताप सिंह	सदस्य
5-श्री ललित कुमार सिंह पुत्र श्री हर्ष बहादुर सिंह	सदस्य
उक्त आदेश तत्काल से प्रभावी होंगे।	

अभिषेक प्रकाश,
जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी,
लखनऊ।

कार्यालय, जिलाधिकारी, झांसी

24 मार्च, 2022 ई०

सं० 167/12ए-डी०एल०आर०सी०/2021-22—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं० 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा टहरौली किला, तहसील टहरौली, जिला झांसी के प्रबन्ध में निहित थी, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झांसी	टहरौली	टहरौली	टहरौली किला (टहरौली)	152 मि० (152/1)	हेक्टेयर 0.405 में से 0.069	श्रेणी-5-3-ड बंजर	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ०प्र०, लखनऊ के निर्वर्तन पर 50 शैय्या फील्ड हास्पिटल के भवन निर्माण हेतु (निःशुल्क)।

01 अप्रैल, 2022 ई०

सं० 181/12ए-डी०एल०आर०सी०/2021-22—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं० 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा गौंती, तहसील गरौठा, जिला झांसी के प्रबन्ध में निहित थी, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झांसी	गरौठा	गरौठा	गौंती	1688 मि०	हेक्टेयर 4.3270	6-4 बेहड़	निराश्रित गौवंश संरक्षण हेतु वृहद गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना (पशुधन विभाग को) (निःशुल्क)।

सं० 182/12ए-डी०एल०आर०सी०/2021-22—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं० 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा गुढ़ा, तहसील गरौठा, जिला झांसी के प्रबन्ध में निहित थी, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झांसी	गरौठा	गरौठा	गुढ़ा	1524	हेक्टेयर 4.5840	श्रेणी-5-3-ड बंजर	निराश्रित गौवंश संरक्षण हेतु वृहद गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना (पशुधन विभाग को) (निःशुल्क)।

सं0 183/12ए-डी0एल0आर0सी0/2021-22—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा धवारी, तहसील टहरौली, जिला झांसी के प्रबन्ध में निहित थी, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झांसी	टहरौली	टहरौली	धवारी	47/1	हेक्टेयर में से 8.8110 5.0000	श्रेणी-5-3-ड बंजर	निराश्रित गौवंश संरक्षण हेतु वृहद गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना (पशुधन विभाग को) (निःशुल्क)।

सं0 184/12ए-डी0एल0आर0सी0/2021-22—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा पठगुवां, तहसील मऊरानीपुर, जिला झांसी के प्रबन्ध में निहित थी, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झांसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	पठगुवां	1011-ख	हेक्टेयर में से 2.8330 2.2230	6-4 बेहड़	निराश्रित गौवंश संरक्षण हेतु वृहद गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना (पशुधन विभाग को) (निःशुल्क)।

13 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 209/12ए-डी0एल0आर0सी0/2021-22—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा पथरेड़ी, तहसील टहरौली, जिला झांसी के प्रबन्ध में निहित थी, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झांसी	टहरौली	टहरौली	पथरेड़ी	55	हेक्टेयर 1.279 में से 0. 28025	श्रेणी-5-3- ड बंजर	जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पेयजल पाईप लाइन बिछाने हेतु बडवार योजना में प्रभावित आरक्षित वन भूमि के बदले गैर वन भूमि (वन विभाग, झांसी को) (निःशुल्क)।

सं0 210/12ए-डी0एल0आर0सी0/2021-22—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा मठ, तहसील झांसी, जिला झांसी के प्रबन्ध में निहित थी, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झांसी	झांसी	झांसी	मठ	348	हेक्टेयर 3.036 में से 0.408	श्रेणी-5-3- ड बंजर	जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पेयजल पाईप लाइन बिछाने हेतु गुलारा, बचावली, तिलैथा एवं बुढ़पुरा योजना में प्रभावित आरक्षित वन भूमि के बदले गैर वन भूमि (वन विभाग, झांसी को) (निःशुल्क)।

सं0 211/12ए-डी0एल0आर0सी0/2021-22—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा कटेरा, तहसील मऊरानीपुर, जिला झांसी के प्रबन्ध में निहित थी, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	कटेरा	58 मि०	1.428 में से 0.512	श्रेणी-5-3- ड बंजर	जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पेयजल पाईप लाइन बिछाने हेतु कुरैछा ग्राम समूह पेयजल योजना में प्रभावित आरक्षित वन भूमि के बदले गैर वन भूमि (वन विभाग, झांसी को) (निःशुल्क)।

सं० 212/12ए-डी०एल०आर०सी०/2021-22-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं० 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा कुरैछा, तहसील मऊरानीपुर, जिला झांसी के प्रबन्ध में निहित थी, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	कुरैछा	684 मि०	2.428 में से 0.600	श्रेणी-5-3- ड बंजर	जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पेयजल पाईप लाइन बिछाने हेतु कुरैछा ग्राम समूह पेयजल योजना में प्रभावित आरक्षित वन भूमि के बदले गैर वन भूमि (वन विभाग, झांसी को) (निःशुल्क)।

जिलाधिकारी,
झांसी।

कार्यालय, जिलाधिकारी, बांदा

31 मार्च, 2022 ई०

सं० 274(5)/12-भूमि व्यवस्था-इस कार्यालय के पुर्नग्रहण आदेश पत्रांक 51/12-भूमि व्यवस्था दिनांक 09 नवम्बर, 2020 के अन्तर्गत मौजा जुगरेहली, तहसील बबेरू स्थित गाटा संख्या 518, रकबा 0.062 हे० को निरस्त करते हुये उसके स्थान पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना

संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अनुराग पटेल, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ 7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बांदा	बंबेरू	जुगरेहली	जुगरेहली	5-1 नवीन परती खाता संख्या 270	559	हेक्टेयर 1.344 में से 0.062	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ०प्र० को अमलीकौर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

22 अप्रैल, 2022 ई०

सं० 276(5)/12-भूमि व्यवस्था-इस कार्यालय के पुर्नग्रहण आदेश पत्रांक 167/12-भूमि व्यवस्था दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 के अन्तर्गत मौजा बबेरू देहात, तहसील बबेरू स्थित गाटा संख्या 4134 मि०, रकबा 0.170 हे० में से 0.100 हे० को निरस्त करते हुये उसके स्थान पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अनुराग पटेल, जिलाधिकारी, बांदा, निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम बबेरू देहात, ग्राम पंचायत बबेरू देहात, तहसील बबेरू, जिला बांदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुये शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिए भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी।
1	2	3	4	गाटा संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर	भूमि की श्रेणी	11
1	बांदा	बबेरू	बबेरू देहात	4118	1.9060 में से 0.3600	श्रेणी-6-4 चारागाह हेतु सुरक्षित भूमि के स्थान पर श्रेणी-5-3-ड बंजर	2444	1.2950 में से 0.3600	श्रेणी-5-3-ड बंजर के स्थान पर श्रेणी-6-4 चारागाह हेतु सुरक्षित भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ०प्र० को अमलीकौर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

27 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 273(5)/12-भूमि व्यवस्था-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, लखनऊ दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अनुराग पटेल, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ 7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/ परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या /भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बांदा	बंबेरू	बबेरू देहात	बबेरू देहात	श्रेणी-5-3-ड बंजर खाता संख्या 3084	3029 मि0	हेक्टेयर 0.085 में से 0.017	होमगार्डस असेम्बली कम रिटायरिंग रूम के निर्माण हेतु।

सं0 274(4)/12-भूमि व्यवस्था-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, लखनऊ दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अनुराग पटेल, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ 7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/ परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या /भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बांदा	नरैनी	सढ़ा	सढ़ा	श्रेणी-5-3-बग बंजर खाता संख्या 2081	3532 मि0	हेक्टेयर 0.0480	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के नवीन भवन निर्माण हेतु।

अनुराग पटेल,
जिलाधिकारी,
बांदा।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 31 दिसम्बर, 2022 ई० (पौष 10, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय नगर पंचायत औरास, जनपद-उन्नाव

30 नवम्बर, 2022 ई०

सं० 278/उपविधि/न०पं०औ०/2022—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ के शासनादेश सं० 6433/नौ-1-96 दिनांक 07 नवम्बर, 1996 एवं नगर पंचायत समिति की बैठक के संकल्प संख्या-08 दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के क्रम में नगर पंचायत औरास-उन्नाव अपनी सीमान्तर्गत मच्छरजनित एवं संक्रामक रोगों की रोक थाम एवं प्रबन्धन निमित्त विनियम उपविधि, 2019 का प्राख्यान करती है, जिसका विस्तार अर्धलिखित है। प्रस्तावित उपविधि पर यदि किसी को कोई भी आपत्ति/सुझाव हेतु दिनांक 18 नवम्बर, 2020 से दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 तक के लिए इस कार्यालय के पत्र सं० 562/उपविधि/न०पं०औ०/2020-21 दिनांक 18 नवम्बर, 2020 के द्वारा दो राष्ट्रीय समाचार-पत्रों दैनिक राष्ट्रीय सहारा व दैनिक आज में प्रकाशित किया गया था। उक्त अवधि में कोई आपत्तियां इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई हैं।

1—(1) यह उपविधि नगर पंचायत (मच्छरजनक) स्थितियाँ पैदा करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही उपविधि, 2019 कहलायेगी।

(2) यह नगर पंचायत की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त मानी जायेगी।

2—परिभाषाएँ—(1) जब तक की सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उपविधि में,

(क) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से है।

3—प्रतिषेध—कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में—

(1) पानी को ऐसे जमा नहीं होने देगा या बहने नहीं देगा कि जिससे मच्छर अपना प्रजनन (ब्रीडिंग) कर सके या उनके उसमें प्रजनन करने की सम्भावना हो।

(2) इस क्षेत्र में न तो खुद पानी जमा होने देगा और न दूसरे को ऐसा करने की इजाजत या अनुमति देगा और न किसी भी प्रकार से पानी को वहां जमाया संचित होने देगा जिसमें मच्छर पैदा होते हो या उनके पैदा होने की सम्भावना हो। ऐसा वह उसी हालत में होने देगा जब उस पानी का इस प्रकार उपचार (ट्रीटमेंट) हो गया हो कि उसमें मच्छर पैदा ही न हो पाये।

4-जन विज्ञापन—किसी भी स्थिर पानी बहते पानी के जल-निकाय (वाटर बाडी) में यदि लावे पाये तो वह इस बात के प्रमाण होंगे कि उस पानी में मच्छरों की ब्रीडिंग हो रही है।

5-(1) नगर स्वास्थ्य अधिकारी जिन रुके हुए या बहते हुए पानी के स्थानों में मच्छर पनप रहे हों, या उनके पनपने की सम्भावना हो, उस सभी के स्वामियों (ओनरों) अभिग्राहियों (आक्यूपायरों) को लिखित नोटिस द्वारा सूचित करके निर्दिष्ट समय में जो (चौबीस घण्टों से कम नहीं) भौतिक रसायनिक अथवा जैविक किसी भी विधि से या अन्य किसी ऐसे उपयुक्त उपाय से जिसे नगर स्वास्थ्य अधिकारी उचित समक्षता हो, उन प्रजनन स्थलों को उपचारित (ट्रीट) करवायेगा।

(2) मच्छरों के प्रजनन स्थलों (ब्रीडिंग प्लेसेज) की कीटनाशक उपचार—यदि उपविधि (क) के अन्तर्गत अभिग्राही आक्यूपायर किरायेदार लीज आदि पर आवास लेने वाले) को नोटिस दिया जाता है और इसके विपरीत में कोई कारनामा व्यक्त (एक्सप्रेसड) या व्यजित (इम्प्लाइड) नहीं हुआ है तो मालिक से उसके द्वारा नोटिस में बताये गये उपायों पर खर्च की गई उचित धनराशि मांग सकता है अथवा उसे किराये में काट सकता है जो उससे मकान मालिक को देना है।

6-व्यतिक्रम अथवा चक्र पर कार्यवाही—यदि उपविधि 5 (1) के अन्तर्गत वह व्यक्ति जिस पर नोटिस जारी किये गये हैं बताये गये उपायों करने से इन्कार कर देता है या नोटिस में निहित उपचार निर्दिष्ट समय में करवा सकता है और इसका खर्चा जैसी भी स्थिति मालिक या किरायेदार से वसूल कर सकता है मानों सम्पत्ति कर का बकाया हों।

7-मच्छर रोधी संरचनाओं की सुरक्षा—किसी भी जमीन पर या भवन में मच्छरों के प्रजनन रोकने के लिए सरकार ने स्थानीय प्राधिकरण या सर्व निर्देश से अभिग्राही (आक्यूपायर) ने यदि कोई नियम करवाया है तो अधिशासी अधिकारी उस जमीन या भवन उपयोग किसी ऐसे काम के लिए रोक सकता है जो मच्छर-रोधी इन संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने या कार्य कुशलता में गिरावाट लाये।

8-मच्छर निवारण/नियंत्रण कार्य में दखल अन्दाजी या हस्तक्षेप पर रोक—अधिशासी अधिकारी की अनुमति बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्मित संरचना या सामग्री या वस्तु से जो उन स्थान पर या उन भवन में मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के लिए मुख्य अधिशासी अधिकारी के आदेश से बनी हो या रखी किसी भी प्रकार की छेड़-छाड़ नहीं करेगा न उसे बिगाड़ेगा, नष्ट करेगा और बेकार करेगा। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस उपविधि का उल्लंघन किया जाता है तो अधिशासी अधिकारी फिर उस रचना (स्ट्रक्चर) को बनवायेगा या उन सामग्री के स्थान पर नई सामग्री रखेगा और उसका खर्च उस व्यक्ति से वसूल करेगा मानों वह सम्पत्ति कर का बकाया हो।

9-प्रत्येक पात्र—घर, भवन रेड (सायबान) या जमीन का मासिक या किरायेदार वहां पर कोई बोतल, बर्तन बाल्टी डिब्बा या अन्य कोई पात्र, साबुत या टूटा हुआ, इस तरह से नहीं रखेगा कि उसने पानी जमा होने की सम्भावना हो या पानी भरा रहे, जिससे उसमें मच्छर पैदा हो।

10-निर्माण कार्य जैसे सड़क निर्माण करने, रेलवे लाइन डालने, घाट बनाने के समय जमीन में खोदे गये गड्ढे (बोर पिट) इस प्रकार होंगे कि उनमें पानी न भरा रहें। जहां भी सम्भव और व्यवहार्य हो, इन बोर पिटों के किनारे को साफ रखा जाये। एक प्रतिशत का अतिरिक्त खर्चा इस काम के लिए किया जाये। बोरपिट के तले में इस प्रकार का ढाल और रूप दिया जाये कि नालियों से पानी एक बोरपिट से निकल कर दूसरे में चला जाये और आखिर में सबसे समीप के नाले में गिर जाये। कोई भी व्यक्ति अलग से कोई बोरपिट नहीं बनवायेगा जिसमें पानी जमा हो और मच्छर पैदा हो।

11-यदि मच्छरों की रोकथाम की किसी योजना को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद हो, या इन उपबन्धों के अन्तर्गत कोई ऐसा निर्माण कार्य हो जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार भी उलझी हो, तो इस मामले में भारत सरकार का फैसला अन्तिम होगा।

12-स्वास्थ्य कर्मचारियों को परिसर (प्रेमिसेज) में प्रवेश करने और निरीक्षण करने का अधिकारी—अधिशासी अधिकारी उचित समय पर लिखित नोटिस या सूचना देने के बाद विवेक सम्मत समय पर घरों में प्रवेश कर सकेगा। अपने क्षेत्राधिकार की किसी जमीन या भवन में प्रवेश और इस या भवन का मालिक या किरायेदार जैसा भी हो, इस प्रवेश और निरीक्षण में अपनी पूरी सहायता देगा और वह सभी जानकारी देगा जिसकी मच्छर जनित रोगों/मलेरिया नियन्त्रण कार्य में जरूरत है।

शास्ति

नगर पंचायत औरास-उन्नाव अपनी सीमान्तर्गत लागू उपविधि के किसी भी पैरा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर आर्थिक दण्ड निर्धारित करते हुए प्रति प्रकरण रु0 200.00 प्रतिदिन दण्ड के रूप में वसूल करेगी। यदि कोई व्यक्ति दण्ड देने में असमर्थ रहता है, तो उसकी वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल करने का अधिकार नगर पंचायत में निहित है।

राकेश कुमार,

अध्यक्ष,

नगर पंचायत औरास, उन्नाव।

30 नवम्बर, 2022 ई0

सं0 279/न0पं0औ0(उपविधियां), वि0क0शु0/प्रकाशन/2022—संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत औरास की सीमा हेतु “विविधकर (शुल्क)” उपविधि नियमावली, 2020 को नगर पंचायत औरास की समिति बैठक दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के संकल्प संख्या-13 में प्रस्तावित करती है। जिसका विस्तार अर्धलिखित है। प्रस्तावित उपविधि पर यदि किसी को कोई भी आपत्ति/सुझाव हेतु दिनांक 24 फरवरी, 2021 से दिनांक 25 मार्च, 2021 तक के लिए इस कार्यालय के पत्रांक-640/न0पं0औ0(उपविधियां), वि0क0शु0/प्रकाशन/2021 दिनांक 22 फरवरी, 2021 के द्वारा दो राष्ट्रीय समाचार-पत्रों दैनिक राष्ट्रीय सहारा व दैनिक अमर उजाला में प्रकाशित किया गया था। उक्त अवधि में कोई आपत्तियां इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई हैं।

विविधकर (शुल्क) नियमावली

1—शीर्षक—यह नियमावली नगर पंचायत औरास उन्नाव “विविधकर (शुल्क) नियमावली, वर्ष 2020 कहलायेगी।

2—प्रकृति—यह नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से या नगर पंचायत समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

3—परिभाषाएँ—जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 एक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) “अधिशासी अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत औरास जनपद उन्नाव के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) “बोर्ड” का तात्पर्य नगर पंचायत औरास जनपद उन्नाव के बोर्ड से है।

(घ) “अध्यक्ष” से तात्पर्य नगर पंचायत औरास जनपद उन्नाव के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

(ङ) “नगर पंचायत” से तात्पर्य नगर पंचायत औरास जनपद उन्नाव से है।

(च) “नगर पंचायत की सीमाओं” से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमाएँ या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

(छ) “फीस” से तात्पर्य नगर पंचायत औरास में वर्णित मदों पर लगायी गई फीस से है।

4—सफाई कर निर्धारण की प्रक्रिया—नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140 के अन्तर्गत परिभाषित वार्षिक मूल्य के आधार पर सफाई कर का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा।

(1) सरकारी भवनों/विद्यालयों/शैक्षिक संस्थानों/प्रतिष्ठानों/मैरिज हाल/गेस्ट हाउसों/धर्मशालाओं पर जो गृहकर, जलकर व सीवर कर की परिधि में है उन पर वार्षिक मूल्य का 08 प्रतिशत सफाई कर देय होगा।

(2) सरकारी भवनों/विद्यालयों/शैक्षिक संस्थानों/प्रतिष्ठानों/मैरिज हाल/गेस्ट हाउसों/धर्मशालाओं पर जो गृहकर, जलकर व सीवर कर की परिधि में है उन पर वार्षिक मूल्य का 12 प्रतिशत सफाई कर देय होगा।

(3) सरकारी भवनों/विद्यालयों/शैक्षिक संस्थानों/प्रतिष्ठानों/मैरिज हाल/गेस्ट हाउसों/धर्मशालाओं पर जो गृहकर, जलकर व सीवर कर की परिधि में है उन पर वार्षिक मूल्य का 22 प्रतिशत सफाई कर देय होगा।

(4) सरकारी भवनों/विद्यालयों/शैक्षिक संस्थानों/प्रतिष्ठानों/मैरिज हाल/गेस्ट हाउसों/धर्मशालाओं पर जो गृहकर, जलकर व सीवर कर की परिधि में है उन पर वार्षिक मूल्य का 22 प्रतिशत सफाई कर देय होगा।

(5) केन्द्र सरकार के स्वामित्व के भवन एवं अर्द्ध सरकारी भवनों पर जिनमें सर्विस चार्ज प्राप्त किया जाता है वहां पर सफाई कर वार्षिक मूल्य का 22 प्रतिशत सफाई कर देय होगा।

5-सफाई कर में छूट-नगर पंचायत औरास के अध्यक्ष को विशेष परिस्थितियों में वार्षिक मूल्यांकन पर छूट देने का विशेष अधिकार होगा।

(1) करदाता द्वारा 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक कर (सफाई कर) जमा करने पर वर्तमान मांग पर 10 प्रतिशत छूट दी जायेगी। 01 अक्टूबर से कोई छूट देय नहीं होगी तथा 31 मार्च देय कर का भुगतान न करने पर बकाया मांग पर 10 प्रतिशत अधिभार अधिरोपित करते हुये अगले वित्तीय वर्ष की मांग निर्धारित की जायेगी।

(2) सफाई व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु समस्त भवन स्वामी/अध्यासी/नागरिकों द्वारा स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिये एवं स्वच्छता बनाये रखने के लिये निम्नवत उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा। उत्तरदायित्वों का निर्वहन न करने पर निर्धारित सफाई कर देना होगा।

क्र.सं.	दायित्व	सफाई कर
1	2	3
1	नगर क्षेत्र के अन्तर्गत सफाई कार्य करने के उपरान्त सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा डालना, कूड़ा फेकना, गंदगी फैलाना, प्रतिबन्धित किया जाता है।	उक्त दायित्व का अनुपालन न करने पर प्रथम प्रकरण में रु0 500.00 व द्वितीय प्रकरण में रु0 1,000.00 व तृतीय प्रकरण में रु0 5,000.00 सफाई कर देय होगा।
2	नगर पंचायत के नाला/नालियों में कूड़ा आदि डालना/फेकना प्रतिबन्धित किया जाता है।	उक्त दायित्व का अनुपालन न करने पर प्रथम प्रकरण में रु0 500.00 व द्वितीय प्रकरण में रु0 1,000.00 व तृतीय प्रकरण में रु0 5,000.00 सफाई कर देय होगा।
3	नगर पंचायत के नाला/नालियों में गोबर/मल-मूत्र, चारा आदि फेकना/बहाना प्रतिबन्धित किया जाता है।	उक्त दायित्व का अनुपालन न करने पर प्रथम प्रकरण में रु0 500.00 व द्वितीय प्रकरण में रु0 1,000.00 व तृतीय प्रकरण में रु0 5,000.00 सफाई कर देय होगा।
4	नगर पंचायत के नाला/नालियों में शौचालयों के मानव मल/मूत्र को सीधे खुले में प्रवाहित करना प्रतिबन्धित किया जाता है।	उक्त दायित्व का अनुपालन न करने पर रु0 10,000.00 का सफाई कर प्रतिमाह देय होगा।

1	2	3
5	नगर पंचायत सीमान्तर्गत सार्वजनिक/व्यक्तिगत स्थान पर कूड़ा/अन्य कोई अवशेष जलाना प्रतिबन्धित किया जाता है।	उक्त दायित्व का अनुपालन न करने पर रु0 5,000.00 का सफाई कर प्रति प्रकरण देय होगा।
6	नगर सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत खुले में शौच करना प्रतिबन्धित किया जाता है।	उक्त दायित्व का अनुपालन न करने पर रु0 500.00 का सफाई कर प्रति प्रकरण देय होगा।
7	नगर क्षेत्र में भवन निर्माण कार्य में प्रयोग के बाद अनुपयोगी सामग्री को सड़क पर डालना प्रतिबन्धित किया जाता है।	उक्त दायित्व का अनुपालन न करने पर प्रति ट्राली रु0 500.00 का सफाई कर प्रति प्रकरण देय होगा।
8	समस्त आवासीय/अनावासीय भवनों/अन्य निर्माण गतिविधियों में जिसमें 25 से अधिक निर्माण श्रमिक/कार्मिक कार्य कर रहे हैं उनके लिये आवश्यक होगा कि उनके द्वारा शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।	उक्त दायित्व का अनुपालन न करने पर रु0 20,000.00 मासिक सफाई कर देय होगा।
9	नगर पंचायत औरास क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त शैलून स्वामी द्वारा व्यक्तियों के बाल काटने के उपरान्त सार्वजनिक स्थान/नालियों में डालने को प्रतिबन्धित किया जाता है।	उक्त दायित्व का अनुपालन न करने पर प्रथम प्रकरण में रु0 100.00 व द्वितीय प्रकरण में रु0 200.00 व तृतीय प्रकरण में रु0 1,000.00 सफाई कर देय होगा।
10	समस्त निवासी समुदाय, संस्थान, होटल एवं रेस्टोरेन्ट जिनके पास 5000 वर्ग मीटर का क्षेत्र है। स्थानीय निकाय के साथ भागीदारी करके नियमानुसार श्रोत स्तर पर ही उत्पादकों द्वारा जनित अपशिष्ट का पृथक्कीकरण सुनिश्चित करेंगे। पृथक्कीकरण अपशिष्ट को भिन्न रूप में संग्रहित किये जाने में सहायता प्रदान करेंगे और पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को या तो अधिकृत अपशिष्ट संग्रहकों को अथवा अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता को सौंपेंगे। जहाँ तक सम्भव हो अपशिष्ट के जैव निम्नीकरणीय (बायोडिग्रेडेबल) अंश को परिसर के अन्दर ही कम्पोस्टिंग अथवा जैव मिथेनेशन के माध्यम से प्रसंस्करित, शोधित व निस्तारित किया जायेगा। अपशिष्ट के अपशिष्ट अंश को स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकों अथवा अभिकरण/संस्था को सौंपा जायेगा।	समस्त निवासी, समुदाय, संस्थान, होटल एवं रेस्टोरेन्ट जिनके पास 5000 वर्ग मीटर का क्षेत्र है। यदि उनके द्वारा सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम 2016 के अनुसार कार्यवाही नहीं की जाती है तो नगर पंचायत औरास द्वारा रु0 1,00,000.00 (एक लाख) मात्र मासिक आधार पर श्रोत स्तर पर ही सम्बन्धित भवन स्वामी/अध्यासी/प्रतिष्ठान के परिसर में उत्पादकों द्वारा जनित अपशिष्ट का पृथक्कीकरण सुनिश्चित करेंगे। पृथक्कीकरण अपशिष्ट को भिन्न रूप में संग्रहित किये जाने में सहायता प्रदान करेंगे और पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को या तो अधिकृत अपशिष्ट संग्रहकों को अथवा अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता को सौंपेंगे। जहाँ तक सम्भव हो अपशिष्ट के जैव निम्नीकरणीय (बायोडिग्रेडेबल) अंश को परिसर के अन्दर ही कम्पोस्टिंग अथवा जैव मिथेनेशन के माध्यम से प्रसंस्करित, शोधित व निस्तारित किये जाने का शुल्क लेगी। उक्त प्रक्रिया का पालन करने, करने वाले समस्त निवासी, समुदाय, संस्थान, होटल एवं रेस्टोरेन्ट जिनके पास 5000 वर्ग मीटर का क्षेत्र है को उक्त निर्धारण सफाई कर देना अनिवार्य होगा। जिन भवन/अध्यासी/प्रतिष्ठान के परिसर में स्वतः व्यवस्था कर ली गयी है उनको उक्त सफाई कर से छूट प्रदान की जायेगी।

1	2	3
11	<p>समस्त निवासी समुदाय, संस्थान, होटल एवं रेस्टोरेन्ट जिनके पास 5000 वर्ग मीटर से 10000 वर्ग मीटर तक का क्षेत्र है। स्थानीय निकाय के साथ भागीदारी करके नियमानुसार श्रोत स्तर पर ही उत्पादकों द्वारा जनित अपशिष्ट का पृथक्कीकरण सुनिश्चित करेंगे। पृथक्कीकरण अपशिष्ट को भिन्न रूप में संग्रहित किये जाने में सहायता प्रदान करेंगे और पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को या तो अधिकृत अपशिष्ट संग्रहकों को अथवा अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता को सौंपेंगे। जहाँ तक सम्भव हो अपशिष्ट के जैव निम्नीकरणीय (बायोडिग्रेडेबल) अंश को परिसर के अन्दर ही कम्पोस्टिंग अथवा जैव मिथेनेशन के माध्यम से प्रसंस्करित, शोधित व निस्तारित किया जायेगा। अपशिष्ट के अपशिष्ट अंश को स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकों अथवा अभिकरण/संस्था को सौंपा जायेगा।</p>	<p>समस्त निवासी, समुदाय, संस्थान, होटल एवं रेस्टोरेन्ट जिनके पास 5000 वर्ग मीटर से 10000 वर्ग मीटर तक का क्षेत्र है। यदि उनके द्वारा सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम, 2016 के अनुसार कार्यवाही नहीं की जाती हैं तो नगर पंचायत औरास द्वारा रु0 2,00,000.00 (दो लाख) मात्र मासिक आधार पर श्रोत स्तर पर ही सम्बन्धित भवन स्वामी/अध्यासी/प्रतिष्ठान के परिसर में उत्पादकों द्वारा जनित अपशिष्ट का पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे। पृथक्करण अपशिष्ट को भिन्न रूप में संग्रहित किये जाने में सहायता प्रदान करेंगे और पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को या तो अधिकृत अपशिष्ट संग्रहकों को अथवा अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता को सौंपेंगे। जहाँ तक सम्भव हो अपशिष्ट के जैव निम्नीकरणीय (बायोडिग्रेडेबल) अंश को परिसर के अन्दर ही कम्पोस्टिंग अथवा जैव मिथेनेशन के माध्यम से प्रसंस्करित, शोधित व निस्तारित किये जाने का शुल्क लेगी। उक्त प्रक्रिया का पालन करने, करने वाले समस्त निवासी, समुदाय, संस्थान, होटल एवं रेस्टोरेन्ट जिनके पास 5000 वर्ग मीटर से 10000 वर्ग मीटर तक का क्षेत्र है को उक्त निर्धारण सफाई कर देना अनिवार्य होगा। जिन भवन/अध्यासी/प्रतिष्ठान के परिसर में स्वतः व्यवस्था कर ली गयी है उनको उक्त सफाई कर से छूट प्रदान की जायेगी।</p>
12	<p>समस्त निवासी समुदाय, संस्थान, होटल एवं रेस्टोरेन्ट जिनके पास 10000 वर्ग मीटर से 15000 वर्ग मीटर तक का क्षेत्र है। स्थानीय निकाय के साथ भागीदारी करके नियमानुसार श्रोत स्तर पर ही उत्पादकों द्वारा जनित अपशिष्ट का पृथक्कीकरण सुनिश्चित करेंगे। पृथक्कीकरण अपशिष्ट को भिन्न रूप में संग्रहित किये जाने में सहायता प्रदान करेंगे और पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को या तो अधिकृत अपशिष्ट संग्रहकों को अथवा अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता को सौंपेंगे। जहाँ तक सम्भव हो अपशिष्ट के जैव निम्नीकरणीय (बायोडिग्रेडेबल) अंश को परिसर के अन्दर ही कम्पोस्टिंग अथवा जैव मिथेनेशन के माध्यम से प्रसंस्करित, शोधित व निस्तारित किया जायेगा। अपशिष्ट के अपशिष्ट अंश को स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकों अथवा अभिकरण/संस्था को सौंपा जायेगा।</p>	<p>समस्त निवासी, समुदाय, संस्थान, होटल एवं रेस्टोरेन्ट जिनके पास 10000 वर्ग मीटर से 15000 वर्ग मीटर तक का क्षेत्र है। यदि उनके द्वारा सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम, 2016 के अनुसार कार्यवाही नहीं की जाती है तो नगर पंचायत औरास द्वारा रु0 3,00,000.00 (तीन लाख) मात्र मासिक आधार पर श्रोत स्तर पर ही सम्बन्धित भवन स्वामी/अध्यासी/प्रतिष्ठान के परिसर में उत्पादकों द्वारा जनित अपशिष्ट का पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे। पृथक्करण अपशिष्ट को भिन्न रूप में संग्रहित किये जाने में सहायता प्रदान करेंगे और पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को या तो अधिकृत अपशिष्ट संग्रहकों को अथवा अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता को सौंपेंगे। जहाँ तक सम्भव हो अपशिष्ट के जैव निम्नीकरणीय (बायोडिग्रेडेबल) अंश को परिसर के अन्दर ही कम्पोस्टिंग अथवा जैव मिथेनेशन के माध्यम से प्रसंस्करित, शोधित व निस्तारित किये जाने का शुल्क लेगी। उक्त प्रक्रिया का पालन करने, करने वाले समस्त निवासी, समुदाय, संस्थान, होटल एवं रेस्टोरेन्ट जिनके पास 10000 वर्ग मीटर से 15000 वर्ग मीटर तक का क्षेत्र है को उक्त निर्धारण सफाई कर देना अनिवार्य होगा। जिन भवन/अध्यासी/प्रतिष्ठान के परिसर में स्वतः व्यवस्था कर ली गयी है उनको उक्त सफाई कर से छूट प्रदान की जायेगी।</p>

1	2	3
13	<p>समस्त निवासी समुदाय, संस्थान, होटल एवं रेस्टोरेन्ट जिनके पास 15000 वर्ग मीटर से 20000 वर्ग मीटर तक का क्षेत्र है। स्थानीय निकाय के साथ भागीदारी करके नियमानुसार श्रोत स्तर पर ही उत्पादकों द्वारा जनित अपशिष्ट का पृथक्कीकरण सुनिश्चित करेंगे। पृथक्कीकरण अपशिष्ट को भिन्न रूप में संग्रहित किये जाने में सहायता प्रदान करेंगे और पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को या तो अधिकृत अपशिष्ट संग्रहकों को अथवा अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता को सौंपेंगे। जहाँ तक सम्भव हो अपशिष्ट के जैव निम्नकरणीय (बायोडिग्रेडेबल) अंश को परिसर के अन्दर ही कम्पोस्टिंग अथवा जैव मिथेनेशन के माध्यम से प्रसंस्करित, शोधित व निस्तारित किया जायेगा। अपशिष्ट के अपशिष्ट अंश को स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकों अथवा अभिकरण/संस्था को सौंपा जायेगा।</p>	<p>समस्त निवासी, समुदाय, संस्थान, होटल एवं रेस्टोरेन्ट जिनके पास 15000 वर्ग मीटर से 20000 वर्ग मीटर तक का क्षेत्र है। यदि उनके द्वारा सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम, 2016 के अनुसार कार्यवाही नहीं की जाती है तो नगर पंचायत औरास द्वारा रु0 4,00,000.00 (चार लाख) मात्र मासिक आधार पर श्रोत स्तर पर ही सम्बन्धित भवन स्वामी/अध्यासी/प्रतिष्ठान के परिसर में उत्पादकों द्वारा जनित अपशिष्ट का पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे। पृथक्करण अपशिष्ट को भिन्न रूप में संग्रहित किये जाने में सहायता प्रदान करेंगे और पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को या तो अधिकृत अपशिष्ट संग्रहकों को अथवा अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता को सौंपेंगे। जहाँ तक सम्भव हो अपशिष्ट के जैव निम्नकरणीय (बायोडिग्रेडेबल) अंश को परिसर के अन्दर ही कम्पोस्टिंग अथवा जैव मिथेनेशन के माध्यम से प्रसंस्करित, शोधित व निस्तारित किये जाने का शुल्क लेगी। उक्त प्रक्रिया का पालन करने, करने वाले समस्त निवासी, समुदाय, संस्थान, होटल एवं रेस्टोरेन्ट जिनके पास 15000 वर्ग मीटर से 20000 वर्ग मीटर तक का क्षेत्र है को उक्त निर्धारण सफाई कर देना अनिवार्य होगा। जिन भवन/अध्यासी/प्रतिष्ठान के परिसर में स्वतः व्यवस्था कर ली गयी है उनको उक्त सफाई कर से छूट प्रदान की जायेगी।</p>
14	<p>समस्त निवासी समुदाय, संस्थान, होटल एवं रेस्टोरेन्ट जिनके पास 20000 वर्ग मीटर से अधिक का क्षेत्र है। स्थानीय निकाय के साथ भागीदारी करके नियमानुसार श्रोत स्तर पर ही उत्पादकों द्वारा जनित अपशिष्ट का पृथक्कीकरण सुनिश्चित करेंगे। पृथक्कीकरण अपशिष्ट को भिन्न रूप में संग्रहित किये जाने में सहायता प्रदान करेंगे और पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को या तो अधिकृत अपशिष्ट संग्रहकों को अथवा अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता को सौंपेंगे। जहाँ तक सम्भव हो अपशिष्ट के जैव निम्नकरणीय (बायोडिग्रेडेबल) अंश को परिसर के अन्दर ही कम्पोस्टिंग अथवा जैव मिथेनेशन के माध्यम से प्रसंस्करित, शोधित व निस्तारित किया जायेगा। अपशिष्ट के अपशिष्ट अंश को स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकों अथवा अभिकरण/ संस्था को सौंपा जायेगा।</p>	<p>समस्त निवासी, समुदाय, संस्थान, होटल एवं रेस्टोरेन्ट जिनके पास 20000 वर्ग मीटर से अधिक का क्षेत्र है। यदि उनके द्वारा सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम, 2016 के अनुसार कार्यवाही नहीं की जाती है तो नगर पंचायत औरास द्वारा रु0 5,00,000.00 (पांच लाख) मात्र मासिक आधार पर श्रोत स्तर पर ही सम्बन्धित भवन स्वामी/अध्यासी/प्रतिष्ठान के परिसर में उत्पादकों द्वारा जनित अपशिष्ट का पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे। पृथक्करण अपशिष्ट को भिन्न रूप में संग्रहित किये जाने में सहायता प्रदान करेंगे और पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को या तो अधिकृत अपशिष्ट संग्रहकों को अथवा अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता को सौंपेंगे। जहाँ तक सम्भव हो अपशिष्ट के जैव निम्नकरणीय (बायोडिग्रेडेबल) अंश को परिसर के अन्दर ही कम्पोस्टिंग अथवा जैव मिथेनेशन के माध्यम से प्रसंस्करित, शोधित व निस्तारित किये जाने का शुल्क लेगी। उक्त प्रक्रिया का पालन करने, करने वाले समस्त निवासी, समुदाय, संस्थान, होटल एवं रेस्टोरेन्ट जिनके पास 20000 वर्ग मीटर से अधिक का क्षेत्र है को उक्त निर्धारण सफाई कर देना अनिवार्य होगा। जिन भवन/अध्यासी/प्रतिष्ठान के परिसर में स्वतः व्यवस्था कर ली गयी है उनको उक्त सफाई कर से छूट प्रदान की जायेगी।</p>

1	2	3
15	सार्वजनिक स्थान/व्यक्तिगत स्थान/सड़क मार्ग पर दूध का चट्टा लगा करके दूध निकालने का कार्य करके नगर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को प्रभावित करना/गंदगी करना, सार्वजनिक मार्ग पर गोबर फैलाना प्रतिबन्धित है।	उक्त कार्य के लिये सफाई व्यवस्था हेतु अतिरिक्त सफाई कर रु0 50.00 प्रति पशु देय होगा।
16	नगर पंचायत औरास क्षेत्र में खुले में सीवर सेक्शन मशीन से नालियों/खुले में शौचालय के अवशेष डालने पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया जाता है।	उक्त कार्य के लिये अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उस पर रु0 5,000.00 जुर्माना नगर पंचायत औरास द्वारा वसूला जायेगा।
17	नगर पंचायत औरास क्षेत्र में इत्र आदि कारखाना में इत्र आदि बनने के उपरान्त बचे हुए अनुपयोगी सामग्री पदार्थ/खस/मेंहदी आदि समग्रियों के अवशेष नालियों में बहाना अथवा सार्वजनिक स्थान पर डालना प्रतिबन्धित किया जाता है।	उक्त दायित्व का अनुपालन न करने पर प्रथम प्रकरण में रु0 500.00 व द्वितीय प्रकरण में रु0 1,000.00 व तृतीय प्रकरण में रु0 5,000.00 सफाई कर देय होगा।
18	धर्मशालाओं में धार्मिक, राजनैतिक, शादी विवाह आदि अन्य गतिविधियां आयोजित की जाती है, जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न किया जाता है। धर्मशालाओं द्वारा शुल्क लिया जाता है। सम्बन्धित भवनस्वामी/प्रबन्धक को सूचना नगर पंचायत औरास को प्रति आयोजन की देनी होगी।	प्रति आयोजन रु0 500.00 सफाई कर देय होगा। आयोजन की सूचना न देने की स्थिति में सफाई कर रु0 1,000.00 देय होगा।
19	मैरेज हाल/गेस्ट हाउस/होटल/बारातघर/स्कूल/कालेज तथा ऐसे अन्य परिसर जहां पर सामूहिक रूप से लोगो को एकत्रित करके कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसके उपरान्त अपशिष्ट उत्पन्न होता है। सम्बन्धित भवन स्वामी/प्रबन्धक को सूचना नगर पंचायत औरास को प्रति आयोजन की देनी होगी।	प्रति आयोजन रु0 5,000.00 सफाई कर देय होगा। आयोजन की सूचना न देने की स्थिति में सफाई कर रु0 10,000.00 देय होगा।
20	समस्त प्रकार के ऐसे भवन प्रतिष्ठान, अनआवासीय परिसर जिनमें 5 से अधिक दुकाने हैं जिनमें व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हैं उनको व्यवसायिक श्रेणी में मानते हुए सम्बन्धित परिसरों में महिला शौचालय प्रसाधन की व्यवस्था छः माह के अन्दर करना अनिवार्य होगा।	ऐसा न करने पर रु0 5,000.00 सफाई कर देय होगा एवं 01 वर्ष पश्चात् शौचालय/प्रसाधन की व्यवस्था न करने पर रु0 5,000.00 प्रति माह देय होगा।

6—नगर पंचायत औरास के सभी हितबद्ध पक्षकार यदि उक्त दायित्वों का पालन नहीं करते हैं तो नगर पंचायत औरास द्वारा अपने स्तर से नगर क्षेत्र के ऐसे समस्त हितबद्ध पक्षकारों का सर्वे कराने का कार्य कर अनुभाग द्वारा करा कर सर्वे उपरान्त एक माह की सूचना सम्बन्धित हितबद्ध पक्षकार को दे कर मांग कायम करने का अधिकार

होगा। उक्त प्रक्रिया को पालन करने के लिये कर अधिकृत/राजस्व निरीक्षक/करसमाहर्ता को अधिकृत किया जाता है उनके न होने पर उक्त दायित्वों का निर्वहन अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वयः किया जायेगा तथा वसूली से सम्बन्धित कार्यवाहियां नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अध्याय 05 के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार अनुमन्य होगी।

शास्ति

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299-307 में दिये गये प्राविधानों के अधीन उक्त नियमावली के किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो जुर्माना रु0 1,000.00 (एक हजार) मात्र रुपये वसूल किया जायेगा और जब ऐसा उल्लंघन निरन्तर किया जाता है तो प्रथम दोष सिद्ध के दिन से प्रत्येक दिन के लिये रु0 25.00 (रुपये पच्चीस मात्र) अतिरिक्त देय होगा तथा 299 व 307 के उपरान्त के उपबन्ध लागू होगा।

7-उ0प्र0 पथ विक्रेता जीविका संरक्षण नियमावली-निदेशक स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0 3/773सा0/पथ विक्रेय/2017 दिनांक 22 मई, 2017 तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सिविल मिस रिट पिटीशन संख्या 53235/2016 दिलीप पासवान बनाम राज्य व अन्य के अनुपालन के क्रम में नगर पंचायत औरास-उन्नाव द्वारा अपने सीमा में फेरी नीति/पथ विक्रेता/जीविका संरक्षण नियमावली की विरचना की जाती है।

नगर पंचायत सीमा में पथकर नियमावली के अनुसार 2×2 वर्ग मीटर ढकेल/रेहड़ी/फड़ आदि लगाने पर निम्न दरें लागू होंगी।

प्रतिदिन दरें	मासिक दरें	वार्षिक दरें
15 रु0 मात्र प्रतिदिन	400 रु0 मात्र मासिक	4000 रु0 मात्र वार्षिक

1-नगर पंचायत औरास की सीमान्तर्गत प्रत्येक रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति को नगर पंचायत को अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

2-नगर पंचायत द्वारा प्रत्येक रेहड़ी लगाने वाले का फोटोयुक्त पहचान-पत्र जारी करेगी।

3-नगर पंचायत द्वारा नियत किये गये स्थान पर ही पथ विक्रेता अपनी रेहड़ी/फड़/ढेला आदि लगा सकेगा।

दण्ड

उ0 प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत औरास-उन्नाव यह आदेश देती है कि इस नियमावली में किसी प्रकार का उल्लंघन करने पर रु0 10,000.00 (दस हजार) मात्र तक आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है और यदि अपराध निरन्तर जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड लगाया जायेगा जो प्रथम दोष सिद्ध होने के दिनांक से यह सिद्ध हो जाने पर किसी अपराधी के द्वारा निरन्तर अपराध जारी रखने पर रु0 100.00 (एक सौ) मात्र प्रतिदिन हो सकता है।

8-नगर पंचायत औरास उन्नाव द्वारा मोबाईल टावर/विद्युत ट्रांसफार्मर/बिजलीघर/कोल्ड स्टोरेज आदि पर शुल्क-

1-नगर पंचायत औरास उन्नाव की सीमान्तर्गत डिश एन्टीना के माध्यम से टीवी प्रसारण किया जाता है या डिश एन्टीना का व्यवसाय किया जाता है।

2-प्रत्येक डिश एन्टीना स्वामी/साझेदारी पर उनके दिये गये कनेक्शनों पर प्रति कनेक्शन रु0 100.00 प्रतिमाह शुल्क लिया जायेगा।

3-डिश एन्टीना स्वामी माह के अन्तिम सप्ताह में संचालित कनेक्शनों की सूची अनिवार्य रूप से कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

4-कनेक्शनों की जांच/निरीक्षण नगर पंचायत के अधिकृत अधिकारी द्वारा कभी भी किया जा सकेगा।

5-केबिल तार इस प्रकार से डाला जाये जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना न हो।

नगर पंचायत औरास उन्नाव द्वारा मोबाईल टावर/विद्युत् ट्रांसफार्मर/बिजलीघर/कोल्ड स्टोरेज आदि पर शुल्क निर्धारण हेतु उपविधियां शासनादेश दिनांक 24 अक्टूबर, 1994 द्वारा निर्धारित कर/शुल्क दरें—

क्रमांक	मद का नाम	शासनादेश दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 द्वारा निर्धारित दरें
1	ट्रांसफार्मर	500.00 रुपये/वर्ष
2	विद्युतगृह	50.00 रुपये/गज
3	कोल्ड स्टोरेज	10,000.00 रुपये/वर्ष
4	मोबाईल टावर	10,000.00 रुपये/वर्ष

दण्ड

उ0 प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत औरास उन्नाव यह आदेश देती है कि इस नियमावली में किसी प्रकार का उल्लंघन करने पर रु0 15,000.00 (पन्द्रह हजार) मात्र तक आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है और यदि अपराध निरन्तर जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड लगाया जायेगा जो प्रथम दोष सिद्ध होने के दिनांक से यह सिद्ध हो जाने पर किसी अपराधी के द्वारा निरन्तर अपराध जारी रखने पर रु0 100.00 (एक सौ) मात्र प्रतिदिन हो सकता है।

राकेश कुमार,

अध्यक्ष,

नगर पंचायत औरास, उन्नाव।

30 नवम्बर, 2022

सं0 280/न0पं0औ0 (उपविधियां), भवन निर्माण/प्रकाशन/2022—संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 एक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 298 सूची (1) उपखण्ड (क), क, ख, ग, घ, ङ., के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत औरास की समिति बैठक दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के संकल्प संख्या-09 के अन्तर्गत ने अपनी सीमा के अन्तर्गत “भवन निर्माण” नियमावली बनायी है। जिसे उक्त एक्ट की धारा 301(1) के अन्तर्गत आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 18 नवम्बर, 2020 से दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 तक के लिए इस कार्यालय के पत्र सं0 563/न0पं0औ0(उपविधियां), भवन निर्माण/प्रकाशन/2020 दिनांक 18 नवम्बर, 2020 के द्वारा दो राष्ट्रीय समाचार-पत्रों दैनिक अमर उजाला व दैनिक आज में प्रकाशित किया गया था। उक्त अवधि में कोई आपत्तियाँ इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। उक्त नियमावली गजट प्रकाशन की तिथि से लागू समझी जाय।

भवन निर्माण नियमावली

1—शीर्षक—यह नियमावली नगर पंचायत औरास उन्नाव “भवन निर्माण” नियमावली, वर्ष 2020 कहलायेगी।

2—प्रकृति—यह नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से या नगर पंचायत समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

3—परिभाषाएँ—जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 एक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) “अधिशाली अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत औरास जनपद उन्नाव के अधिशाली अधिकारी से है।

(ग) “बोर्ड/समिति” का तात्पर्य नगर पंचायत औरास जनपद उन्नाव के बोर्ड/समिति से है।

(घ) “अध्यक्ष” से तात्पर्य नगर पंचायत औरास जनपद उन्नाव के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

(ङ) “नगर पंचायत” से तात्पर्य नगर पंचायत औरास जनपद उन्नाव से है।

(च) “नगर पंचायत की सीमाओं” से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

4-नोटिस-कोई भी व्यक्ति जो नगर पंचायत औरास की सीमा के अन्तर्गत किसी भवन अथवा भूमि का स्वामी हैं और उसे किराये पर देने और विक्रय करने अथवा पट्टे पर देने का हक रखता है तो वह उस पर निर्माण, पुनः निर्माण या परिवर्तन करना चाहता है तो वह उक्त एक्ट की धारा 178 के अन्तर्गत नगर पंचायत से निर्धारित शुल्क जमा कर फार्म क्रय करके सम्बन्धित फार्म पर अधिशासी अधिकारी को एक लिखित नोटिस देगा।

5-प्लान-इस प्रकार के नोटिस के साथ जो कि किसी भवन के निर्माण पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन से सम्बन्धित है मानचित्र और विवरण दो प्रतियों में संलग्न करेगा। मानचित्र ट्रेसिंग क्लार्क एवं ब्लू प्रिंट पर हो सकते हैं। उपर्युक्त नोटिस तक अमान्य समझा जायेगा। जब कि सम्बन्धित व्यक्ति यह नोटिस नहीं देता है कि उसने उस शुल्क का भुगतान नगर पंचायत औरास कर दिया है। जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न करनी होगी यदि किसी कारण से नगर पंचायत द्वारा भवन का मानचित्र अस्वीकृत कर दिया जाता है और शुल्क जो अदा कर दिया गया है वह भवन स्वामी को मानचित्र की स्वीकृति के दिनांक से एक वर्ष के भीतर नगर पंचायत द्वारा सम्पूर्ण आपत्तियों के अनुमोदन के पश्चात् बिना शुल्क अपने भवन के मानचित्र को प्रेषित करने की आज्ञा दी जायेगी यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा रख-रखाव किये जाने वाली सड़क के किनारे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दूरी के भीतर किसी प्रकार निर्माण पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन करना चाहता है तो वह दो प्रतियों में नोटिस देगा और नोटिस के साथ नक्शे प्राप्त होने पर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत औरास नोटिस एवं नक्शे की दो प्रति सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास नोटिस देने के लिए भेजेगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग का वह पदाधिकारी नोटिस प्राप्त होने के दो सप्ताह के अन्दर इस बात की सूचना नगर पंचायत औरास को देगा कि उन्हें इस निर्माण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है या नहीं यदि उक्त पदाधिकारी नगर पंचायत को दो सप्ताह के निर्दिष्ट अवधि के अन्दर कोई सूचना प्रेषित नहीं करते हैं तो ऐसे मामलों में यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित निर्माण पर कोई आज्ञा प्रदान कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6-इस प्रकार प्रस्तुत सभी नक्शे 01 सेमी0 बराबर 1 मीटर के पैमाने पर सही ढंग से खींचे होने चाहिए और स्केल मानचित्र पर अंकित होनी चाहिये और उत्तरी रेखा भी नक्शे पर दर्शानी चाहिये मानचित्र पर प्रार्थी के हस्ताक्षर होने चाहिये तथा मानचित्र पर निम्न विवरण दर्शाना चाहिए।

(क) मानचित्र में उस भू-खण्ड से मिली हुई सम्पूर्ण गलियों, सड़क की चौड़ाई परिमाण तथा आधार दर्शाना चाहिये तथा भू-खण्ड के निकट गुजरने वाली बिजली के तारों का उल्लेख भी होना चाहिये। मानचित्र से उस भू-खण्ड की चौहद्दी भी साफ-साफ दर्शानी चाहिये तथा उस भू-खण्ड के चारों ओर के भवन स्वामियों के नाम मानचित्र में दर्शाने चाहिये।

(ख) मानचित्र से शटर और परनाले का गन्दे पानी की निकास की नालियों का उल्लेख होना चाहिए।

(ग) आवश्यक सेवाओं का सही स्थानापन्न जैसे शौचालय स्नानगार आदि का स्पष्ट उल्लेख मानचित्र में होना चाहिए।

(घ) मानचित्र में निम्न बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

(1) भूतल और उससे मिली हुई नालियों, सड़कों और गैर इस्तेमाली स्थानों का विवरण।

(2) सड़कों का परिमाण एवं उन कमरों के इस्तेमाल का विवरण जैसा कि शयनकक्ष, रसोई घर, शौचालय आदि।

(3) भूतल, प्रथम तल और अतिरिक्त तल।

(4) मानचित्र में भवन का फ्रन्ट एलिवेशन दर्शाना चाहिए।

(5) कुर्सी का लेबिल तथा अभिन्यास प्लान से लगी सड़को का लेबिल।

(6) दरवाजो, खिड़कियों तथा वेन्टीलेटरी का प्रकार एवं माप।

(7) सामग्री का प्रकार जिससे कि बुनियाद दीवारें, छते तथा फर्श का निर्माण होना है।

(ङ) प्रस्तावित एवं वर्तमान कार्यो को विभिन्न रंगों से स्वच्छता के साथ दिखाना चाहिए

जैसे प्रस्तावित लाल रंग से वर्तमान कार्य बैंगनी रंग से परनाला तथा नालियों को नीले रंग से तथा अन्य व्यक्तियों की सम्पत्ति को पीले रंग से दर्शाना चाहिए।

(च) भवन मानचित्र में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लान भी दर्शाना होगा।

7-शुल्क उपनियम 5 में दर्शाया गया मानचित्र पर निम्न शुल्क अदा करना होगा-

1	2	3	4
		भूतल प्रति वर्ग फिट	अतिरिक्त तल (प्रति) प्रति वर्ग फिट
1	निवासी भवन (कवर्ड एरिया)	6.00	3.00
2	निवासी भवन (ओपेन एरिया)	4.00	2.00
3	व्यवसायिक भवन दुकान (कवर्ड एरिया)	30.00	15.00
4	व्यवसायिक भवन (ओपेन एरिया)	20.00	10.00
5	वर्कशाप, फ़ैक्ट्री, कारखाना आदि	30.00	15.00
6	वर्कशाप, फ़ैक्ट्री, कारखाना आदि (ओपेन एरिया)	25.00	10.00

नोट—शुल्क स्टेशनरी शुल्क के रूप में जमा किया जायेगा जो कि भवन मानचित्र जमा करने के समय जमा किया जायेगा। भवन मानचित्र अस्वीकृत होने की दशा में जमा शुल्क का 25 प्रतिशत धनराशि स्टेशनरी शुल्क के रूप में रोक ली जायेगी तथा 75 प्रतिशत धनराशि वापस कर दी जायेगी।

1—प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य भवन का कवर्ड एरिया एवं ओपन एरिया पर निर्धारित शुल्क होगा।

2—इस शुल्क में ट्रेसिंग क्लार्क का मूल्य शामिल नहीं है।

3—नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 181 के अन्तर्गत यह स्वीकृति एक वर्ष हेतु मान्य होगी।

4—(क) कोई भी भवन कच्चा, पक्का या पूर्णतः पक्का हो सकता है।

(ख) सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन स्वीकृत नहीं किया जायेगा प्रोजेक्शन हेतु प्रोजेक्शन नियमावली के अन्तर्गत पृथक से आवेदन करना होगा।

(ग) भू-तल पर सड़क को और खुलने वाले दरवाजे (किवाड़) भीतर की तरफ रहेंगे।

(घ) प्रस्तावित निर्माण यदि सार्वजनिक सड़क के किनारे किया जाता है तो सड़क की पटरी से 1.20 मीटर चौड़ा स्थल छोड़कर निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी।

5—धार्मिक स्थल—मस्जिद, मन्दिर, चर्च, गुरुद्वारा इसी प्रकार के अन्य धार्मिक स्थलों की स्वीकृति उस समय तक नहीं दी जायेगी जब तक कि वह स्थलों के बीच से 7.50 मीटर की दूरी पर न हो तथा प्रस्तावित धार्मिक किसी अन्य धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी के भीतर निर्माण नहीं किया जायेगा।

6—बिजली के तार बिजली के तारों से दूरी 30 फीट पावर कार्पोरेशन एक्ट और उसमें समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों में उल्लेखित दूरी के अन्तर्गत किसी भी इमारत में बरामदा, छज्जा, साहेबान या ऐसी किसी प्रकार की चीज का नवनिर्माण, पुर्ननिर्माण अथवा परिवर्तन की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

7—शौचालय एवं गन्दे पानी का निकास—ऐसे व्यक्ति जो भवन का निर्माण स्थान करेगा जो कि सार्वजनिक नालों से 30 मीटर के भीतर होगा तो उसे अपने भवन के पानी को नाली को सार्वजनिक नाली, तक स्वयं मिलाना होगा।

8—भवन में फ्लैश/लैट्रीन लगाना अनिवार्य होगा बिना फ्लैश/लैट्रीन के मानचित्र की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

- 9—नालियां भवन की नालियां सीमेन्ट कंकरीट द्वारा मजबूत व पक्की नालियां बनाई जायेगी तथा सार्वजनिक नालियों से इसका जोड़ा होना भवन स्वामियों के लिए आवश्यक होगा।
- 10—बरसाती पानी के छतों से उतरने हेतु पाइप लगाने होंगे।
- 11—पिलिन्थ (कुर्सी)—भवन का पिलिन्थ भवन के सामने की सड़क से कम से कम 0.50 मीटर ऊँचा रखना होगा।
- 12—भवन की ऊँचाई—भूतल पर फर्श से छत पर ऊँचाई 3.60 मीटर तथा ऊपर के अन्य तलों पर कम से कम 3.00 मीटर रखनी होगी।
- 13—(क) भवन की किनारे—व्यक्तियों के रहने के कमरों का क्षेत्रफल कम से कम 7.20 वर्गमीटर होगा तथा कमरे की चौड़ाई कम से कम 2.40 मीटर रखी जायेगी।
- (ख) कमरों में समुचित जंगलों और वेन्टीलेशन की व्यवस्था करनी होगी जो कि खुले स्थान में होंगे तथा इनका क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल से 01/01 से कम नहीं होगा।
- (ग) जंगले इस प्रकार बनाये जायेंगे कि इनको पूरा खोला जा सके।
- (घ) जीना—बहु मंजिले भवनों के हवादार जीने का निर्माण आवश्यक होगा।
- 14—(क) किसी ऐसे भू-खण्ड पर निवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी जिसकी चौड़ाई 7.50 मीटर तथा लम्बाई (गहराई) 12.00 मीटर से कम न होगी।
- (ख) किसी भी ऐसे भू-खण्ड पर निवासीय भवन की स्वीकृति नहीं दी जायेगी जहां पर कूड़ा व गन्दे पदार्थों का ढेर लगाया जाता हो तब तक कि स्वास्थ्य अधिकारी/अधिशासी अधिकारी उसके लिए अपनी स्वीकृति न दे दें।
- 15—जानवरों का बाड़ा—जानवरों के बाड़े में फर्श पक्का एवं ढालदार बनाना होगा।
- 16—(क) नक्शा स्वीकृत करने से पहले भू-खण्ड के सम्बन्ध में राजस्व विभाग से कर विभाग से आख्या ली जायेगी।
- (ख) स्वास्थ्य अधिकारी/स्वास्थ्य निरीक्षक/या जैसी स्थिति हो से रोशनी एवं वेन्टीलेशन एवं शौचालय आदि के आख्या आदि के पश्चात् नक्शा स्वीकृत किया जायेगा।
- (ग) जब अधिशासी अधिकारी वह इत्मीनान कर लेगा कि प्रस्तावित भवन इन नियमों से सम्बन्धित सभी शर्तों को पूरी करता है तो वह मानचित्र को स्वीकृति प्रदान करेगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सार्वजनिक मार्गों पर किसी भी प्रकार के प्रोजेक्शन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (घ) यदि अधिशासी अधिकारी प्रस्तावित मानचित्र में कोई संशोधन करता है तो उसका कारण दोनों प्रतियों में दर्ज करेगा इसकी एक प्रति कार्यालय में रहेगी।
- 17—शासन/जिला/उच्चाधिकारियों से समय-समय पर निर्गत आदेशों के क्रम में नियमावली उस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

शास्ति

संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 एक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत औरास जनपद-उन्नाव यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र) तक हो सकता है। यदि निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 25.00 (रुपय पच्चीस मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

राकेश कुमार,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत औरास, उन्नाव।

कार्यालय नगर पंचायत कछौना पतसेनी, जनपद-हरदोई

16 अक्टूबर, 2022 ई0

सं0 387/न0पं0 कछौना/बायलॉज/2021-22-उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128(1)व 126(10) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई ने अपनी बोर्ड बैठक 24 फरवरी, 2021 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी भवनों, इमारतों तथा भूमियों पर गृहकर निर्धारण हेतु शासनादेश सं0-408/नौ-10-63ज/95टी0सी0 नगर विकास अनुभाग-9 दिनांक 22 फरवरी, 2010 व शासनादेश सं0-135/नौ-9-11-190-द्वि0रा0वि0आ0/04 लखनऊ दिनांक 18 मार्च, 2011 के अनुपालन में नगर पंचायत कछौना पतसेनी हरदोई की सीमान्तर्गत भवनों व सम्पत्तियों पर स्वकर प्रणाली के अंतर्गत गृहकर निर्धारण किये जाने हेतु स्वमूल्यांकन व्यवस्था प्रभावी तथा संपत्तियों पर गृहकर निर्धारण नियमावली, 2019 बनायी गयी है जो राजकीय गजट में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावी होगी। उक्त उपविधि के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो अपनी आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई के कार्यालय में विज्ञप्ति प्रकाशन के एक माह अर्थात् 30 दिन के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

सम्पत्तियों पर गृहकर निर्धारण नियमावली, 2019

1—यह नियमावली नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई की सीमा में स्थित भवनों तथा सम्पत्तियों पर गृहकर निर्धारण नियमावली, 2019 कही जायेगी।

2—यह नियमावली नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई की सीमा में लागू होगी।

3—यह नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशन के पश्चात् इसी वित्तीय वर्ष 2019-20 से लागू होगी।

4—“नगर पंचायत” से तात्पर्य नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई से है।

5—“अधिशाली अधिकारी” से तात्पर्य नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई के अधिशाली अधिकारी से है।

6—“अध्यक्ष” से तात्पर्य नगर पंचायत के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है।

7—“प्रशासक/बोर्ड” का तात्पर्य नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई के प्रशासक बोर्ड से है।

8—“अधिनियम” से तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

9—“शासनादेश” का तात्पर्य उ0प्र0 भासन के आदेशों/निर्देशों से है।

10—कोई भी व्यक्ति यदि नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई की सीमा में भवन/भूमि का स्वामी/अध्यासी है तो वे भवन/भूमि के सम्पत्ति कर निर्धारण स्वमूल्यांकन द्वारा कर लेंगे। इसके लिए नगर पंचायत गोपामऊ, हरदोई से एक आवेदन-पत्र प्राप्त कर अपने मकान का ब्यौरा देकर उपविधि में दी गयी निर्धारित दर के अनुसार स्वकर का निर्धारण करेंगे।

11—आवेदन-पत्र नगर पंचायत कछौना पतसेनी से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

12—जिन भवन/भूमि स्वामी/अध्यासी द्वारा स्वकर निर्धारण का विकल्प नहीं अपनाया जायेगा तो उसके सम्बन्ध में कर का निर्धारण व वसूली की कार्यवाही नियमानुसार नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई द्वारा की जायेगी।

13—भवन—इसमें वह सभी अहातें, उपघर आदि एक संयुक्त परिसर में कई भवन स्थित है तो इस परिसर के सभी इमारतों के परिसर को भूमि सहित भवन कहा जायेगा और मकान का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा में अंकित परिभाषा से है।

14—“सम्पत्ति” का तात्पर्य किसी भवन/भूमि या दोनों से है।

15—“आच्छादित क्षेत्रफल” का तात्पर्य, कुर्सी के उपर जिसपर भवन निर्मित है के प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्रफल से है।

16—कारपेट एरिया की गणना नियमानुसार की जायेगी—

(क) कमरे	—आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप।
(ख) आच्छादित बरामदा	—आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप।
(ग) बालकनी, कारीडोर, रसोई व भण्डार गृह	—आन्तरिक आयाम की 50 फीसदी माप।
(घ) गैराज	—आन्तरिक आयाम की 1/4 माप।
(ङ) स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने से आच्छादित क्षेत्र	—कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

अथवा

कारपेट एरिया —आच्छादित क्षेत्र का 80 प्रतिशत भाग।

17—कर का निर्धारण—कर का निर्धारण निम्नांकित के आधार पर किया जायेगा।

(क) वार्षिक मूल्य की गणना, वार्षिक मूल्य = कारपेट एरिया × निर्धारित प्रति ईकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12

या

आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत × निर्धारित प्रति ईकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12

18—करों का भुगतान—

(क) अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी/कर्मचारी बनाये गये नियम के अधीन निर्धारित भवन/भूमि (सम्पत्ति) कर के भुगतान हेतु स्वामी/अध्यासी को बिल भेजेगा, जिसमें एक ऐसा दिनांक निर्दिष्ट होगा, नगर पंचायत कछौना पतसेनी कार्यालय अथवा उसके द्वारा अभिसूचित बैंक में कर का भुगतान किया जायेगा। गृहकर निर्धारण का भुगतान का सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किये जाने पर भी निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। निर्धारित अवधि के नियमावली में दी गयी शास्ति तथा उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 173 (क) के अनुसार कर की वसूली की जायेगी। धारा 173 (क) की कार्यवाही का खर्च तथा बकाया धनराशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लिया जायेगा।

(ख) यह है कि नगर पंचायत की ओर से अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी जैसे भी परिस्थिति हो के नगर पालिका अधिनियम की धारा 158(1)(2) के अन्तर्गत पत्र भेजकर किसी भवन/भूमि स्वामी को उनके सम्पत्ति आदि के बारे में विवरण प्रस्तुत करने तथा अन्य दस्तावेज मांगने व प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(ग) इस उपविधि के किसी भी प्रावधान के बारे में नगर पंचायत यदि संतुष्ट है कि उपविधि के किसी प्रावधान का दुरुपयोग पंचायत द्वारा किया जा रहा है अथवा कोई प्रावधान/नियमानुसार जनहित में नहीं है, तो उक्त प्रावधान को निरस्त करने, छूट देने अथवा संशोधित करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा।

19—किराये पर उठे आवासीय भवनों का उपरोक्तानुसार अवधारित वार्षिक मूल्य से (ARV) जोड़ें।

(क) दस वर्ष से अधिक पुराना है तो 25 प्रतिशत अधिक होगा (+) 25 प्रतिशत

(ख) दस वर्ष से अधिक तथा बीस वर्ष से कम पुराना है तो 12.5 प्रतिशत अधिक होगा (+) 12.5 प्रतिशत

(ग) बीस वर्ष से अधिक पुराना हैं तो यथावत समझा जायेगा।

नोट—नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140(2) में यह प्रावधान है कि जहाँ नगर पंचायत किराये में किसी कारण से असाधारण परिस्थितियों में किसी भवन का वार्षिक मूल्य यदि उपर्युक्त रीति से गणना की गई हो अत्यधिक हो वहाँ नगर पंचायत किसी भी धनराशि पर जो भी न्याय संगत प्रतीत हो वार्षिक मूल्य नियमित कर सकती है।

20—व्यावसायिक सम्पत्तियों से तात्पर्य—सभी प्रकार की फुटकर दुकानें, शोरूम, बेकरी, आटाचक्की, कोयला, लकड़ी, कृषि उपकरणों के लिये केन्द्र, शीतगृह, रिजोर्ट, होटल व बेवसाइट व ऑटोमोबाइल शोरूम/सर्विस सेन्टर व भोजनालय, जलपानगृह, रेस्टोरेन्ट, कैन्टीन, सिनेमा व मल्टीप्लेक्स, अस्थाई सिनेमा, पी0सी0ओ0, पेट्रोल व डीजल फिलिंग स्टेशन, गोदाम/गैस अधिष्ठान भण्डारण तथा गोदाम, निजी कार्यालय, बैंक व अन्य अनावासीय भवनों से है।

21—औद्योगिक सम्पत्तियों से तात्पर्य—सेवा/कुटीर उद्योग, औद्योगिक कारखाने, पावरलूम कारखाना, सूचना प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी/एल0पी0जी0 व फिलिंग प्लाण्ट/संयंत्र/केन्द्र आदि से है।

22—इन्स्टीट्यूशनल (संस्थागत) सम्पत्तियों से तात्पर्य—राजकीय, अर्द्धराजकीय, स्थानीय निकाय कार्यालय, श्रमिक कल्याण केन्द्र, पी0ए0सी0, पुलिस लाइन, मौसम अनुसंधान केन्द्र, वायरलेस केन्द्र, अतिथि गृह, धर्मशाला, रैनबसेरा, लॉजिंग बोर्डिंग हाउस, छात्रावास, अनाथालय, सुधारालय, कारागार, हेण्डिकैप चिल्ड्रेन हाउस, शिशुगृह, एवं देखभाल केन्द्र, वृद्धावस्था केन्द्र, प्राथमिक शैक्षिक संस्थान, उच्चतर माध्यमिक इण्टर/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, पोलीटेक्निक, इन्जिनियरिंग, विशिष्ट शैक्षिक संस्थान, आई0टी0आई0, डाकघर, तारघर, पुलिस स्टेशन/चौकी, अग्निशमन केन्द्र, पुस्तकालय/वाचनालय, नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, कलाकेन्द्र, सिलाई केन्द्र, बुनाई कढ़ाई केन्द्र, पेन्टिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि, ऑडिटोरियम, नाट्यशाला, थियेटर, योगकेन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, धर्मिक केन्द्र, बारात घर, कॉन्फ्रेंस एवं मीटिंग हाल, प्रदर्शनी केन्द्र, रेडियों व टेलीविजन कार्यालय/केन्द्र, नर्सिंग होम व अस्पताल आदि।

नोट—जो भी सामाजिक, धर्मिक राजनैतिक संस्थायें निःशुल्क जनहित में कार्य कर रही हैं वे कर से मुक्त रहेगी परन्तु जिस धर्म/राजनैतिक संस्था का जितने भाग का उपयोग व्यवसायिक होगा उस पर कर देय होगा।

23—रेन्ट कन्ट्रोल के मकान—रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम, 1972 के अधीन आने वाले आवासीय भवनों पर नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई प्रत्येक करों की गणना के लिये वार्षिक किराये का निर्धारण रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम के अंतर्गत नहीं होगा बल्कि गृहकर का निर्धारण उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 के प्रावधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-135/9-9-11-190-द्वि0रा0वि0आ0/04 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 18 मार्च, 2011 के अनुसार किया जायेगा।

24—जिन भवनों/व्यावसायिक भवनों में भवन स्वामी का पता नहीं चलता है तो ऐसे भवनों में किरायेदार/अध्यासी को की गृहकर का भुगतान करना होगा।

25—करों में छूट—

(क) गृहकर की देयता वार्षिक होगी, 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य संबंधित वर्ष का कर जमा करना अनिवार्य होगा।

(ख) सम्बन्धित वर्ष में कर जमा नहीं करने की दशा में आगामी वित्तीय वर्ष में गृहकर पर 10 प्रतिशत की दर से सरचार्ज देय होगा।

26—संबंधित संसूचना प्रपत्र (क) प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर नगर पंचायत कार्यालय में भरकर जमा करना अनिवार्य है। भवन के क्षेत्रफल एवं दरों के सम्बन्ध में कोई त्रुटि पूर्ण विवरण होने की दशा में स्वामी अध्यासी से सम्पत्ति की देयता में होने वाले अन्तर के चार गुने धनराशि शास्ति (जुर्माना) के रूप में ली जायेगी निर्धारित अवधि तक विवरण न जमा करने की दशा में 50 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 400 वर्ग मीटर तथा उससे अधिक भू-खण्ड पर क्रमशः रु0 100/500/1000/3000 तक शास्ति (जुर्माना) आरोपित करके वसूल किया जायेगा, तथा 30 दिन के विलम्ब की स्थिति में शास्ति (जुर्माना) का 5 प्रतिशत अतिरिक्त लिया जायेगा।

27—भवन किराये पर देने या रिक्त होने, भवन में निर्माण/पुनर्निर्माण होने से आच्छादित क्षेत्रफल (कारपेट एरिया) में वृद्धि होने पर तथा भवन के व्यावसायिक/औद्योगिक प्रयोग होने पर 60 दिनों के अन्दर प्रपत्र (ख) में ही पुनः विवरण भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

28—जिन भवनों/भूमियों को नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई द्वारा भवन/भूमि की संज्ञा दी जा चुकी है उन्हें भी प्रपत्र क और ख पर उपरोक्तानुसार सूचना भरकर जमा करना अनिवार्य है तथा उसके भवन/भूमि पर यदि कोई पूर्व का बकाया है तो प्रपत्र क के अनुसार देय कर एवं पूर्व बकाया भी जमा करेंगे।

29—मकानों को दर्ज करने सम्बन्धी—

(क) कोई भी व्यक्ति किसी भी समय यदि किसी भी भवन या भूमि पर अपना नाम अध्यासी अथवा स्वामी के रूप में करदाता सूची में अंकित कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन करना होगा और यदि उसके नाम के सम्बन्ध में कोई आवेदन निरस्त करते हुये विचाराधीन है तो उल्लेख लिखित रूप में किया जायेगा अन्यथा उसके बाद सूची में आवेदन के अनुसार नाम, कर निर्धारण सूची में अंकित कर दिया जायेगा।

(ख) गृहकर पंजिका में दर्ज ऐसी भूमि/भवन जो पंचायत के स्वामित्व की भूमि है जो किसी कारणवश निजी उपयोग में लायी जा रही है तो वह गृहकर पंजिका में स्वतः निरस्त/करमुक्त मानी जायेगी।

30—मकानों का हस्तांतरण सम्बन्धी नियम—

(क) यदि किसी भवन या भूमि जिस पर कर आरोपित है स्वामित्व हस्तांतरित होता है तो स्वामित्व हस्तांतरित करने वाले व्यक्ति तथा संस्था अथवा स्वामित्व पाने वाला व्यक्ति ऐसे संस्था ऐसे हस्तांतरण के 03 माह के अन्दर उसकी सूचना नगर पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके निर्धारित प्रपत्र पर अधिशासी अधिकारी को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि किसी करदाता अथवा भवन/भूमि के स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस को मृत्यु के दिनांक से 03 माह के अन्दर लिखित सूचना रु0 300.00 शुल्क जमा करके अधिशासी अधिकारी को देना होगा।

(ग) यदि किसी करदाता अथवा भवन का वारिस/उत्तराधिकारी 03 माह के अन्दर सूचना देने में असफल रहता है तो 03 माह के बाद प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते समय उसे नामान्तरण शुल्क के साथ रु0 100.00 विलम्ब शुल्क भी देय होगा तभी प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही किया जायेगा। यही प्रक्रिया विक्रय-पत्र के आधार पर नामान्तरण को कार्यवाही पर भी लागू होगी।

(घ) विक्रय-पत्र के आधार पर आवेदक नगर पंचायत अभिलेखों में दर्ज कराना चाहता है तो उसका शुल्क रु0 500.00 जमा करने के बाद ही कार्यवाही शुरू की जायेगी।

31—कर निर्धारण दर—गृहकर वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत तथा जलकर वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत देय होगा।

32—मुख्य मार्ग का तात्पर्य—मुख्य मार्ग में सभी सड़कें आयेंगी जिसकी चौड़ाई 12 मीटर से अधिक होगी।

33—अन्य मार्ग का तात्पर्य—मुख्य मार्ग के अंदर के मार्ग व मोहल्ला/कालोनी में जाने वाली सड़क एवं समस्त गलियां अपने भागों में आयेंगी।

34—अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई द्वारा सत्यापित मासिक किराया प्रति वर्गफुट।

35—अन्तिम निर्णय अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई में निहित होगा।

36—अन्य व्यावसायिक भवन/मिश्रित भवन जो मुख्य मार्ग पर स्थित न हो का कर निर्धारण निर्धारित आवासीय दर का दोगुना दर पर किया जायेगा।

37—(क) किसी भी स्वामी द्वारा अध्यासित आवासीय भवन जो 30 वर्ग मी0 के माप वाले या 15 वर्ग मी0 तक कारपेट क्षेत्रफल भू-खण्ड पर निर्मित हो उसके स्वामी के स्वामित्व में नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई की सीमा के अंतर्गत कोई अन्य भवन/भू-खण्ड न हो पर वार्षिक मूल्य की गणना नहीं की जायेगी वो कर से मुक्त होंगे।

(ख) यदि आंशिक भाग का उपयोग व्यावसायिक/औद्योगिक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और आंशिक भाग पर निवासित है तो व्यावसायिक/औद्योगिक वाले भाग पर व्यावसायिक/औद्योगिक दर लागू होगा तथा निवासित भाग पर निवासित दर लागू होगा।

(ग) व्यावसायिक/औद्योगिक उपयोग वाले आवासों/आवासीय अंशों पर कर निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा।

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासीय भवन की मासिक किरायें की दर
1.	प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्पलेक्स, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान बैंक, कार्यालय, होटल, कोचिंग व प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त को छोड़कर) आवासीय सह दुकान की स्थिति में।	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का पांच गुना
2.	टावर और होर्डिंग वाले भवन, टी0बी0 टावर दूर संचार या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते हैं।	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का चार गुना
3.	प्रत्येक प्रकार के क्लीनिक, पाली क्लीनिक डायग्नोस्टिक केन्द्र, प्रयोगशालायें, नर्सिंग होम, चिकित्सालय केन्द्र, मेडिकल स्टोर, स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र।	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का तीन गुना
4.	पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो और गोदाम	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर कातीन गुना
5.	सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप शादी/बारात घर, क्लब व इसी प्रकार के भवन	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का तीन गुना
6.	औद्योगिक इकाइयां सरकारी अर्धसरकारी एवं सार्वजनिक, उपक्रम कार्यालय	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का तीन गुना
7.	क्रीडा केन्द्र, जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र, थियेटर तथा सिनेमा घर	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का दो गुना
8.	अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणियों में उल्लिखित नहीं हैं।	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का तीन गुना
9.	छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान जो अधिनियम की धारा 129-क के खण्ड (ग) के अधीन आच्छादित नहीं हैं।	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर के समान

38—अधिशाली अधिकारी नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई द्वारा पंचायत सीमान्तर्गत स्थित भवनों/भूमियों का वार्षिक मूल्यांकन दरों पर निर्धारित किया जायेगा।

कक्षवार (वार्डवार) निर्धारित प्रस्तावित मासिक किराया (प्रति वर्ग फीट) दरों की सूची

कक्ष/ वार्ड का नाम	वार्ड संख्या	24 फीट से अधिक चौड़े मार्ग पर दर			20 फीट 24 फीट चौड़े मार्ग पर दर			12 फीट से कम चौड़े मार्ग पर दर			भूमि के सम्बन्ध में	
		आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	12 फीट से 24 फीट चौड़े मार्ग पर दर	12 फीट से कम चौड़े मार्ग पर दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अम्बेडकर नगर	1	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
काशी नगर	2	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
सदर बाजार	3	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
रेलवेगंज पश्चिमी	4	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
ठाकुरगंज नटपुरवा	5	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
कछौना पतसेनी चौराहा पश्चिमी	6	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
तिलक नगर	7	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
रेलवेगंज पूर्वी	8	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
इमलीपुर	9	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
कछौना पतसेनी चौराहा पूर्वी	10	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
कछौना बाजार पश्चिमी	11	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05
कछौना बाजार पूर्वी	12	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05

अर्थदण्ड

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई निश्चित करती है कि उपविधि के किसी भी नियम का उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध होगा जो रु0 1000.00 एक हजार जुर्माना हो सकता है और निरन्तर बने रहने की दशा में अतिरिक्त अर्थदण्ड देय होगा जो सर्वप्रथम दोष सिद्ध के दिनांक या अधिशासी अधिकारी द्वारा दिये गये नोटिस के दिनांक से प्रत्येक दिवस के लिये जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि जिसमे अपराधी अपराध करता है, रु0 25.00 (पच्चीस रुपये) मात्र प्रतिदिन अर्थदण्ड लिया जायेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगर पंचायत कछौना पतसेनी,
जनपद-हरदोई।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं आलोक दुबे पुत्र रमाशंकर दुबे, केशवपुर सरपतहां जिला भदोही का मूल निवासी हूँ। त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट के अंक विवरणिका सह प्रमाण-पत्र में मेरे पिता का नाम कलट्टर दुबे एवं माता का नाम आराधना देवी अंकित हो गया है परन्तु मेरे पिता का सही नाम रमाशंकर दुबे एवं मेरे माता का सही नाम साधना देवी है। भविष्य में मेरे प्रत्येक शैक्षणिक दस्त्तावेजों एवं हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट के अंक विवरणिका सह प्रमाण-पत्र में मेरे माता-पिता को उनके सही नाम साधना देवी तथा रमाशंकर दुबे के नाम से जाना व पहचाना जाये।

आलोक दुबे।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का सही नाम जन प्रकाश सिंह है जो उनके शैक्षिक अभिलेखों आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे दसवी सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के सह अंक प्रमाण-पत्र में जय प्रकाश सिंह अंकित हो गया है उपरोक्त दोनों नाम मेरे पिता का ही है भविष्य में मेरे पिता को उनके सही नाम जन प्रकाश सिंह पुत्र रामचंद्र सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये। ज्ञानवी सिंह पुत्री जन प्रकाश सिंह साकिन 105 उमा नगर, देवरिया खास, देवरिया।

ज्ञानवी सिंह,
पुत्री जन प्रकाश सिंह।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम पूर्व में आर्यन अवस्थी था लेकिन स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपने पुत्र का नाम बदलकर मनय अवस्थी रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को मनय अवस्थी पुत्र वीरेन्द्र कुमार अवस्थी के नाम से जाना व पहचाना जायें।

वीरेन्द्र कुमार अवस्थी,
पुत्र कमल कुमार अवस्थी,
म0नं0 134/244, बशीरतगंज,
लखनऊ-226004।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म मे0 मंगलम सर्विस स्टेशन-60 स्टेनली रोड, प्रयागराज के भागीदार श्रीमती आइरिस हेनरी व आशीष हेनरी दिनांक 12 जुलाई, 2022 को उक्त फर्म से अपनी भागीदारी समाप्त करते हुए अलग हो गये हैं अब फर्म में श्री विजय कुमार वैश्य केवल एक ही भागीदार है। अतः फर्म भागीदारी अधिनियम के अनुसार स्वतः विघटित हो गयी है। फर्म का व्यवसाय श्री विजय कुमार वैश्य के

प्रोपराइटरशिप में उक्त दिनांक के पश्चात् संचालित होगा। फर्म से अलग हुए भागीदारों का फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन-देन तथा दायित्व शेष नहीं हैं। दिनांक 12 जुलाई, 2022 के पश्चात् दोनों पृथक् हुए भागीदारों का फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का विधिक अधिकार तथा दावा नहीं होगा।

विजय कुमार वैश्य,
भागीदार।

सूचना

मेरी फर्म ओम ट्रांसपोर्ट, तुरा, पिपरी सोनभद्र में मेरे अलावा दो अन्य पार्टनर जिसमें मनोज कुमार पांडेय व स्वर्गीय ओम प्रकाश पांडेय है, जिसमें से ओम प्रकाश पांडेय ने तबियत खराब होने पर 27 जुलाई, 2021 को सेवानिवृत्ति ले ली थी जिसके बाद 24 अगस्त, 2021 को उनकी मृत्यु हो गई है। अब इस फर्म में मैं और मनोज कुमार पांडेय बचे हैं। अतुल कुमार पांडेय पुत्र स्व0 ओम प्रकाश पांडेय तुरा पिपरी सोनभद्र।

अतुल कुमार पांडेय।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सी0बी0 सिंह कोल्ड स्टोरेज, ग्राम-करथिया, पोस्ट मौधा, मोहम्मदाबाद, जिला फर्रुखाबाद के पते से पंजीकृत है जिसका पंजी0 सं0-के-11693 पर दिनांक 24 मई, 2016 को पंजीकृत है। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 26 अप्रैल, 2016 के अनुसार फर्म में श्री चन्द्र पाल सिंह, श्री वीरेन्द्र पाल सिंह, श्रीमती संयोगिता सिंह, श्रीमती नीरज सिंह, श्री प्रवीण कुमार सिंह, श्री पवन कुमार सिंह साझीदार थे। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 25 नवम्बर, 2022 के अनुसार साझीदारी से साझीदार श्री वीरेन्द्र पाल सिंह व श्रीमती नीरज सिंह स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं एवं संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 25 नवम्बर, 2022 के अनुसार अब फर्म में श्री चन्द्र पाल सिंह, श्रीमती संयोगिता सिंह, श्री प्रवीण कुमार सिंह व श्री पवन कुमार सिंह भागीदार हैं।

चन्द्रपाल सिंह,
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स कम्फोर्ट एयरकण्डिशनिंग एण्ड रेफ्रिजरेशन इंजीनियर्स मोहल्ला खोट्टा टोला, पोस्ट-कूड़ाघाट, जनपद-गोरखपुर की साझीदारी में कृष्णदेव कुमार व कपिलदेव साझीदार थे। दिनांक 11 मई, 2018 को रीना देवी पत्नी कृष्णदेव कुमार फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुईं तथा कपिलदेव फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब-किताब लेकर अलग

हो गये। दिनांक 11 मई, 2018 की संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार कृष्णदेव कुमार व रीना देवी साझीदार हैं। तथा फर्म पर किसी का कोई बकाया नहीं है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री कपिलदेव पूर्व साझीदार की मृत्यु दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 को हो चुकी है। यह घोषणा करता हूँ कि एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकता स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

साझीदार,
कृष्णदेव कुमार,
मेसर्स काम्फोर्ट एयरकण्डीशनिंग एण्ड
रेफ्रिजरेशन इंजीनियर्स, मो0-खोट्टा टोला,
पोस्ट-कूडघाट, जनपद-गोरखपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स हंस इण्टरप्राइजेज, 64, पीताम्बर खेरा, जिला उन्नाव की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है फर्म में तीन साझेदार श्रीमती जगरानी देवी पत्नी श्री दौलतराम हंस, श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री दौलतराम हंस, एवं श्री राकेश कुमार पुत्र श्री दौलत राम हंस साझेदार थे जिसमें से श्री सन्तोष कुमार का दिनांक 26 अप्रैल, 2021 को निधन हो गया है तथा इनके स्थान पर दिनांक 18 नवम्बर, 2022 से एक नये साझेदार श्रीमती सुषमा हंस पत्नी श्री सन्तोष कुमार हंस शामिल हो गयी हैं। वर्तमान में श्रीमती जगरानी देवी, श्रीमती सुषमा हंस एवं श्री राकेश कुमार फर्म में साझेदार हैं। जिसकी सूचना दी जा रही है।

साझेदार,
श्रीमती जगरानी देवी,
साझेदार हंस इण्टरप्राइजेज,
जिला-लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स नारायण आटोमोबाइल्स, 4, शाहनजफ रोड, जिला-लखनऊ की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है फर्म में 06 साझेदार श्री राजीव नारायण पुत्र स्व0 गोपाल नारायण, श्री मुदित नारायण पुत्र स्व0 गोपाल नारायण, श्रीमती सावित्री नारायण पत्नी स्व0 गोपाल नारायण, श्रीमती अंकुर नारायण पुत्र पत्नी श्री मुदित नारायण, श्रीमती संध्या नारायण पत्नी श्री राजीव नारायण, श्री राघव नारायण पुत्र श्री राजीव नारायण साझेदार थे दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से श्री सात्विक नारायण पुत्र श्री मुदित नारायण नये शामिल

हुये हैं दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को श्री प्रद्युत नारायण पुत्र श्री मुदित नारायण नये शामिल हुये हैं तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से श्रीमती देवांशी नारायण पत्नी श्री राघव नारायण फर्म में नये शामिल हुये हैं। वर्तमान में श्री राजीव नारायण, श्री मुदित नारायण, श्रीमती सावित्री नारायण, श्रीमती अंकुर नारायण, श्रीमती संध्या नारायण, श्री राघव नारायण, श्री सात्विक नारायण, श्री प्रद्युत नारायण, श्रीमती देवांशी नारायण को मिलाकर कुल 09 फर्म में साझेदार है। जिसकी सूचना दी जा रही है।

साझेदार,
राजीव नारायण,
नारायण आटोमोबाइल्स, 4, शाहनजफ रोड,
जिला-लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स ए0के0 ट्रेडर्स, पता-शोप नं0-2, के0एन0 मोदी कॉम्प्लेक्स, नियर पंजाब नेशनल बैंक, मोदीनगर, जिला-गाजियाबाद पंजीकरण संख्या-28591-M की संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 के अनुसार सभी साझीदारों की आपसी सहमती से फर्म साझीदार-श्रीमती ममता अपनी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गयी है व नवीन साझीदार की हैसियत से श्रीमती वन्दना गुप्ता को फर्म साझेदारी में सम्मिलित किया गया है व फर्म का पता परिवर्तित कर सी-3, कॉवरी एन्क्लेव, मोदीपोन कालोनी रोड, मोदीनगर गाजियाबाद उ0प्र0 किया गया है। फर्म में वर्तमान साझीदार-1. श्री अजय कुमार, 2. श्रीमती माया देवी, 3. श्रीमती वन्दना गुप्ता है।

साझेदार,
अजय कुमार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म, मेसर्स शिव कुमार जायसवाल, 80, राजेन्द्र नगर, लखनऊ 226004 रजि0 नं0-LUC/0003074 का पंजीकरण दिनांक 04 अप्रैल, 2019 को कराया गया था एवं संशोधन 6 अगस्त, 2022 को कराया गया था, जिसमें शिव कुमार जायसवाल प्रथम, आशा जायसवाल द्वितीय, लवी जायसवाल तृतीय साझीदार थे, जिसमें प्रथम साझीदार शिव कुमार जायसवाल दिनांक 02 दिसम्बर, 2022 से फर्म की साझेदारी से हट गये हैं, उक्त तिथि से पूर्व प्रथम साझेदार का भविष्य में कोई लेना-देना नहीं होगा। एवं वर्तमान में फर्म की साझेदारी में श्रीमती मीरा जायसवाल एवं नमन जायसवाल को तृतीय एवं चतुर्थ साझेदार के रूप में रखा गया है। वर्तमान में उक्त फर्म में आशा

जायसवाल प्रथम, लवी जायसवाल द्वितीय, मीरा जायसवाल तृतीय एवं नमन जायसवाल चतुर्थ साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं। तथा फर्म का नाम परिवर्तित करके मेसर्स एस0के0जे0 कान्स्ट्रक्शन कर दिया गया है।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

साझेदार,

आशा जायसवाल,

मेसर्स-शिव कुमार जायसवाल।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेसर्स कुक-डू-कू दुकान नं0-124, ब्लॉक-2, गंगा शापिंग काम्पलैक्स, सेक्टर-29, नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर-201301 की साझेदारी दिनांक 18 अप्रैल, 2013 के अनुसार फर्म में श्री रमित खन्ना एवं श्री रोहित खन्ना साझेदार थे। दिनांक 31 मार्च, 2021 को श्री रोहित खन्ना फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गये हैं। दिनांक 31 मार्च, 2021 फर्म श्री रमित खन्ना की प्रोपराइटरशिप में संचालित है। यह घोषणा करता हूँ कि एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

प्रोपराइटर,

रमित खन्ना,

मेसर्स कुक-डू-कू दुकान नं0-124,

ब्लॉक-2, गंगा शापिंग काम्पलैक्स, सेक्टर-29, नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर-201301।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेसर्स सिंह सिक्थोरिटी सर्विसेज, सी-7, सेक्टर-12, नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर-201301 की साझेदारी दिनांक 21 मार्च, 2009 के अनुसार श्री सुनील प्रताप सिंह, श्रीमती ललिता सिंह एवं श्रीमती हेमलता सिंह थे। दिनांक 09 अक्टूबर, 2022 को साझेदार श्रीमती ललिता सिंह का स्वर्गवास होने के कारण फर्म की संशोधित साझेदारी दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 के अनुसार श्री सुनील प्रताप सिंह एवं श्रीमती हेमलता सिंह साझेदार हैं। यह घोषणा करता हूँ कि एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

साझेदार,

सुनील प्रताप सिंह,

मेसर्स सिंह सिक्थोरिटी सर्विसेज,

सी-7, सेक्टर-12, नोएडा,

जिला-गौतमबुद्धनगर-201301।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स-एस0पी0 हेल्थकेयर, 127/201, डब्लू-1, साकेत नगर, कानपुर 208014 के पते से पंजीकृत है जिसका पंजी0सं0 KAP/0011904 पर दि0 10 मई, 2022 को पंजीकृत है। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 10 जनवरी, 2022 के अनुसार फर्म में डा0 श्रुति सिंह व श्रीमती प्रेमिता देवी साझेदार थे। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 04 अक्टूबर, 2022 के अनुसार साझेदारी में श्री अंकित कटियार को शामिल किया गया है तथा साझेदार श्रीमती प्रेमिता देवी स्वेच्छा से पृथक् हो गयी है। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 के अनुसार अब फर्म में डा0 श्रुति सिंह व श्री अंकित कटियार भागीदार हैं।

पार्टनर,

डा0 श्रुति सिंह।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स-ए0एस0 हेल्थकेयर, 127/201, डब्लू-1, साकेत नगर, कानपुर 208014 के पते से पंजीकृत है जिसका पंजी0सं0 KAP/0011905 पर दि0 10 मई, 2022 को पंजीकृत है। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 10 जनवरी, 2022 के अनुसार फर्म में डा0 शैलेश कुमार व डा0 अमित कुमार कटियार साझेदार थे। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 के अनुसार साझेदारी में श्री सुबोध कटियार को शामिल किया गया है तथा साझेदार डा0 अमित कुमार कटियार स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 के अनुसार अब फर्म में डा0 शैलेश कुमार व श्री सुबोध कटियार भागीदार हैं।

पार्टनर,

डा0 शैलेश कुमार।

सूचना

सर्वविदित हो कि मेरा नाम मीना चौधरी पुत्री सियाराम चौधरी है जो कि मेरे सभी दस्तावेजों में अब तक अंकित है। विवाहोपरान्त अब मैंने अपना नाम बदलकर अपने पति के नामानुरूप मीना सिंह रख लिया है। ये दोनों नाम एक ही महिला के हैं। भविष्य में हर कार्य के लिए मुझे इसी नाम (मीना सिंह) से जाना-पहचाना जाय। मीना सिंह पत्नी लवसिंह निवासिनी-26ए/53ए/2 लाउडर रोड, जार्जटाउन, प्रयागराज।

मीना सिंह।

सूचना

सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स गुप्ता बिल्डर्स, मण्डी जवाहर गंज शामली जिला शामली, उत्तर प्रदेश की यह फर्म जो क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबन्धक, फर्म्स सोसायटीज तथा चिट्स सहारनपुर मण्डल सहारनपुर (उ0प्र0), द्वारा रजिस्टर्ड फर्म है। रजिस्ट्रेशन संख्या 399(S) है। जिसमें भागीदारी डीड के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल, 2014 में निम्न भागीदार थे। (1) श्री सतीश चन्द गुप्ता (HUF) पुत्र स्व0 सुखबीर सिंह, निवासी मण्डी जवाहर गंज शामली, जिला शामली (उ0प्र0)। (2) श्रीमती मनीषा गुप्ता पत्नी स्व0 विशाल गुप्ता, निवासी मण्डी जवाहर गंज शामली, जिला शामली, (उ0प्र0)। (3) श्रीमती अंजली गुप्ता पत्नी श्री आशीष गुप्ता, निवासी मण्डी जवाहर गंज, शामली जिला शामली, (उ0प्र0)। (4) श्रीमती उमा गुप्ता पत्नी श्री सतीश चन्द गुप्ता, निवासी मण्डी जवाहर गंज, शामली जिला शामली, (उ0प्र0)। (5) श्रीमती पारुल गुप्ता पत्नी श्री राहुल गुप्ता, निवासी मण्डी जवाहर गंज, शामली जिला शामली, (उ0प्र0)। (6) श्रीमती सुमन गुप्ता पत्नी स्व0 रमेश चन्द गुप्ता, निवासी मण्डी जवाहर गंज, शामली जिला शामली, (उ0प्र0)। भागीदार फर्म में पार्टनर श्री सतीश चन्द गुप्ता (HUF) पुत्र स्व0 सुखबीर सिंह, निवासी मण्डी जवाहर गंज, शामली जिला शामली, (उ0प्र0)। बतौर पार्टनर थे। उनकी मृत्यु दिनांक 07.10.2020 को हो गयी थी। उनके स्थान पर दिनांक 08.10.2020 को उनके पुत्र श्री राहुल गुप्ता पुत्र स्व0 सतीश चन्द गुप्ता, निवासी मण्डी जवाहर गंज, शामली जिला शामली, (वास्ते श्री सतीश चन्द गुप्ता HUF) को भागीदार पार्टनर बनाया गया है। वर्तमान में अब निम्न भागीदार है। (1) श्रीमती मनीषा गुप्ता पत्नी स्व0 विशाल गुप्ता, निवासी मण्डी जवाहर गंज शामली, जिला शामली (उ0प्र0)। (2) श्रीमती अंजली गुप्ता पत्नी श्री आशीष गुप्ता, निवासी मण्डी जवाहर गंज शामली, जिला शामली, (उ0प्र0)। (3) श्रीमती उमा गुप्ता पत्नी स्व0 सतीश चन्द गुप्ता, निवासी मण्डी जवाहर गंज, शामली जिला शामली, (उ0प्र0)। (4) श्रीमती पारुल गुप्ता पत्नी श्री राहुल गुप्ता, निवासी मण्डी जवाहर गंज, शामली जिला शामली, (उ0प्र0)। (5) श्रीमती सुमन गुप्ता पत्नी स्व0 रमेश चन्द गुप्ता, निवासी मण्डी जवाहर गंज, शामली जिला शामली, (उ0प्र0)। (6) श्री राहुल गुप्ता पुत्र स्व0 सतीश चन्द गुप्ता (वास्ते श्री सतीश चन्द गुप्ता HUF) निवासी मण्डी जवाहर गंज, शामली जिला शामली, (उ0प्र0)।

पार्टनर
सुमन गुप्ता पत्नी
स्व0 रमेश चन्द गुप्ता,
मैसर्स गुप्ता बिल्डर्स।

NOTICE

I Harshit Pandey, have changed the name of my daughter from Himakshi Pandey to Gungun Pandey, From now onwards she would be known and called as Gungun Pandey in any future documentation. Add: D-171 Indira Nagar Lucknow.

Harshit Pandey.

NOTICE

It is notified that from date November 10, 2022 the Principal Place of business/Registered Office of the Firm M/S J.S.G.D.R.R. CONSTRUCTION having Registered Office at 122, Chandganj Garden, Sector-B, Aliganj, Lucknow. (Registration No.-LUC/0011565, Dated April 2, 2022) had changed. The new Principal Place of business/Registered Office of the abovesaid firm is now at VILLAGE-LANGHANIYA, POST-NASIRPUR ANDUPUR, BAGHA DHACK, SITAPUR, U.P.-261201. Any partner have no objection.

That I also certify that all the legal formalities for the abovesaid firm have been completed by me.

Partner,
Himanshu Yadav,
J.S.G.D.R.R. CONSTRUCTION
New Registered Office- VILLAGE-
LANGHANIYA, POST-NASIRPUR
ANDUPUR, BAGHA DHACK,
SITAPUR, U.P.-261201.

NOTICE

It is notified that from date December 08, 2022. The M/s. "A.D.V.G. Associates" Registered Office at B-40 Sector P, Aliganj, Lucknow, (Regd. no. -200876, Dated February 02, 2016) had been dissolved with the consent of both partners. That I have no objection in dissolution of the abovesaid firm.

That I also certify that all the legal formalities for the dissolution of the firm have been completed by me.

Partner,
Anju Gupta,
M/s. "A.D.V.G. Associates",
Registered Office B-40 Sector P,
Aliganj, Lucknow.

NOTICE

It is notified that one partner (Fourth Part) Smt. Ram Jatti in the Firm- M/s. PATEL INDUSTRIES having Registered Office at Village-Daulatyarpur, Madhoganj, Distt.-Hardoi, (Regd. no. -I-188361, Dated May 10, 2005) had untimely expired on date November 01, 2022. No new partner had been inducted in the abovesaid Firm. Now there are four partners at present in the Firm for that any partner have no objection.

That I also certify that all the legal formalities for the abovesaid firm have been completed by me.

Partner,
Mr. Umesh Chandra,
M/s. PATEL INDUSTRIES,
Registered Office-Village-
Daulatyarpur, Madhoganj,
Distt.-Hardoi.

NOTICE

It is notified that one partner (Third Part) Mr. Anil Agarwal in the Firm- M/s. SAI INFRA having Registered Office at MS-91, Sector-D, Aliganj, Lucknow-226024 (U. P.), (Regd. no. LUC/0004027, Dated July 17, 2019) had resigned on date October 01, 2022. No new partner had been inducted in the abovesaid Firm. Now there are three partners at present in the Firm for that any partner have no objection.

That I also certify that all the legal formalities for the abovesaid firm have been completed by me.

Partner,
Mr. Vishal Mehrotra,
M/s. SAI INFRA,
Registered Office-MS-91, Sector-D,
Aliganj, Lucknow-226024 (U. P.)